लोक नीति शोध केन्द्र
PUBLIC POLICY RESEARCH CENTRE

‘कर्मनिष्ठ’ दिल्ली नगर निगम

लोक नीति शोध केंद्र

मार्गदर्शन:
डॉ. सुमीत भसीन

संपादन:
अवनी सबलोक
दीपा कौशिक
सत्यजीत लांडागे
नैन्सी शर्मा
प्रतीक गुधाते

फरवरी, 2022

विषय सूची

01	भूमिका	04
02	प्रस्तावना	06
03	स्वच्छ दिल्ली	07
04	शिक्षा	10
05	स्वास्थ्य	16
06	हरित दिल्ली	19
07	प्रदूषण मुक्त दाह संस्कार	21
08	लैंडफिल साइटों का भार कम किया गया	22
09	स्वच्छ ऊर्जा	22
10	नागरिक केंद्रित शासन	25
11	व्यवस्थित पार्किंग और यातायात प्रबंधन	28
12	कोविड-19 के दौरान पहल	30
13	संदर्भ	34

भूमिका

भारत का शहरी शासन और उसका परिदृश्य पिछले कुछ दशकों में काफी विकसित हुआ है। इस विकास ने एक अधिक आकांक्षी समाज की ओर हमें आगे बढ़ाया है। जो बेहतर सुविधाओं और बेहतर शासन की इच्छा रखता है एवं एक ऐसी व्यवस्था जो नागरिकों के जीवन को आसान बनाती है। हालांकि, दुर्भाग्य से भारत के शहरी स्थानीय निगमों की स्थिति पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। निगमों द्वारा सफल प्रयोगों को समझने के लिए भी बहुत कम काम हुआ है। नतीजतन, इन निगमों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों की बहुत कम जानकारी हमारे पास है, जो देश भर में अन्य शहरी निगमों के लिए सहयोगी हो सकती हैं। जिसके माध्यम से यह निगम स्वयं को सुधारने और अपने नागरिकों के जीवन में बदलाव लाने का प्रायस कर सकते हैं।

देखा जाए तो शहरी निगम नागरिकों के साथ संपर्क के पहले बिंदु के रूप में कार्य करते हैं, उनमें सुधार करना महत्वपूर्ण है। शहरी स्थानीय निगमों की शासन व्यवस्था पर रोशनी डालने के लिए हमने दिल्ली नगर निगम के कार्यों का विश्लेषण किया है। संसद ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 को इसलिए पारित किया था क्योंकि एक तो यह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था और साथ ही यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता था। इसलिए, प्रशासनिक कारणों से बेहतर शहरी शासन महत्वपूर्ण था। इसके बाद 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत शहरी स्थानीय निकायों के विकेन्द्रीकरण और उन्हें सशक्त बनाने के लिए और अधिक शक्तियों का हस्तांतरण किया गया।

दिल्ली के अनुभव का हमारा अध्ययन एक निरंतर प्रक्रिया है - जिसमें हमने एक अनूठा दृष्टिकोण अपनाया है। हमें एक दशक से अधिक के कार्यों का विशलेष किया हैं और दिल्ली के नगर निगमों के शासन परिदृश्य में बदलाव को समझने का प्रयास किया हैं। 'दिल्ली टैंजिबल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट' शीर्षक नामक रिपोर्ट तैयार करने के दौरान पीपीआरसी शोधकर्ताओं ने जमीन पर काम किया, विशेषज्ञों के साथ बातचीत की और 2 साल (2010-2012) की अवधि में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण किया। 2013 में इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग, सार्वजनिक पार्कों एवं खेल मैदानों के प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट, नगरपालिका बाजारों में सुधार के साथ शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण किया। इस रिपोर्ट में तीनों दिल्ली नगर निगमों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया।

एक दशक बाद, अब हम दिल्ली के शहरी शासन पर फिर से एक नजर डाल रहे हैं और उन पहलों का मूल्यांकन कर रहे है, जो सफल साबित हुई, जिससे इन पहलों का लाभ अन्य निगमों को भी मिल सके। यह रिपोर्ट शहरी शासन की बदलती प्रकृति को स्वीकार करती है और इसलिए विश्लेषण करते समय उसी पर ध्यान केंद्रीत किया गया है। इस प्रकार इसे न केवल पिछली रिपोर्ट के विस्तार के रूप में देखा जाना चाहिए, बल्कि दिल्ली में स्थानीय शहरी शासन के मूल्यांकन और पिछले दशक के बाद इसमें आये परिवर्तन के रूप में देखा जाना चाहिए।

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में तीनों निगमों के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। इससे भी आगे तीनों निगम पर्यावरण को लेकर भी बेहद जगरुक नजर आते है, इसको लेकर निगमों द्वारा विभिन्न पहले की गयी है, जिसमें स्क्रैप सामग्री एवं टूटे हुए पेड़ का प्रयोग कर बेंच, झूलों और यहां तक कि कलाकृतियों में परिवर्तित किया, एमसीडी ने दिल्ली के सतत् विकास के लिए सर्वोत्तम कार्य किये है। जो पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी है। इसके अलावा, नगर निगम स्तर पर सहभागी शासन को बढ़ावा देकर नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने का भी सफल प्रयास किया गया है।

विशेष रूप से प्रभावशाली बात यह है कि नगर निगम के सामने संसाधनों की गंभीर कमी है। नगर निगम को धनराशि हस्तांतरित करने में अत्यधिक देरी के कारण और दिल्ली सरकार के साथ तनातनी ने भी निगमों की कार्यशैली पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डाला। इन परिस्थितियों में भी निगमों ने सीमित संसाधनों में बेहतर कार्य करके दिखया है। इसके अलावा, संसाधनों की कमी के बावजूद टैक्स दरों को नहीं बढ़ाया गया। वास्तव में नगर निगमों ने अतिरिक्त संसाधन उत्पन्न करने के लिए विभिन्न पहलों के माध्यम से कर अनुपालन में सुधार के लिए व्यापक प्रयास किए हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निगमों ने क्षमता और गुणवत्ता दोनों को सुनिश्चित किया है, जिससे बुनियादी सार्वजनिक सुविधाओं तक हर नागरिक की पहुंच बन सके, बजाय इसके कि वे कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रहे। जो प्राथमिक विद्यालयों में गतिविधि-आधारित शिक्षा शुरू करने के प्रयास में दिखाई दे रहा है, जिसमें अधिकांश छात्र निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इस तरह के हस्तक्षेप छात्रों की रुचि को बढ़ाते हैं, उनके सीखने की प्रक्रिया में सुधार करते हैं और ड्रॉप-आउट दर को भी कम करने में सहयोगी साबित होते हैं। इस तरह के हस्तक्षेपों को हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के अंतर्गत समर्थन दिया

गया है।

महामारी के दौरान अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत को स्वीकार किया चाहिए, चाहे वह डॉक्टर हों या चिकित्सा कर्मचारी। उनकी निरंतर सेवा के लिए हम उनके ऋणी हैं।

दिल्ली के नगर निगमों में फ्रंट-लाइन कर्मचारियों का एक ऐसा ही एक समूह है— 'सफाई कर्मचारी' जिन्होंने पूरी लगन के साथ चौबीसों घंटे काम किया, यहां तक कि जब महामारी के दौरान अन्य लोग ने स्वयं को अपने घरों तक सीमित कर लिया था, तब भी इन कर्मचारियों ने शहर में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए पूरी लगन के साथ काम किया। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और घातक महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई में उनके योगदान की सराहना करते है।

मैं लोक नीति शोध केंद्र (पीपीआरसी) के शोधकर्ताओं के प्रयासों की भी सराहना करता हूं जिन्होंने दिल्ली के नगर निगमों द्वारा किए गए प्रयासों को प्रकाश में लाने का कार्य किया और उनके द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रतिबिंबित किया।

डॉ. सुमीत भसीन

निदेशक

लोक नीति शोध केन्द्र

प्रस्तावना

"जो लोग स्थानीय बोर्डों और नगर पालिकाओं में प्रतिनिधियों के तौर पर जाते हैं, उनको सम्मान की तलाश या आपसी प्रतिद्वंद्विता में शामिल नहीं होना चाहिए, वह सेवाभाव से कार्य करें और पैसे पर उनकी निर्भरता नहीं होनी चाहिए"

महात्मा गांधी

नगर निगम एक नागरिक निकाय है जो स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। इसके अधिकांश सदस्य सीधे वयस्क मताधिकार से चुने जाते हैं। नगर निगम को 74वें संशोधन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, जो स्थानीय विकास के लिए योजना तैयार करने और विकास परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निगम द्वारा लागू ज्यादात्तर कार्यक्रम शहरी गरीबी उन्मूलन या नागरिक कल्याण के लिए डिजाइन तैयार किये जाते है। नगर निगम सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड, स्वच्छता जिसमें अपशिष्ट प्रबंधन, सीवेज, जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण, सार्वजनिक सुरक्षा, उद्यान या भवन रखरखाव आदि के लिए जिम्मेदार है।

नई दिल्ली क्षेत्र - सभी प्रमुख सरकारी भवनों, कार्यालयों, आवासीय परिसरों और राजनयिक मिशनों का घर - नई दिल्ली नगर परिषद के अंतर्गत आता है जिसमें पूर्व, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली के तीन नगर निगम शामिल हैं। पूर्व, दक्षिणी और उत्तरी नगर निगम के कार्य मुख्य रूप से देश भर के अन्य निगमों के समान हैं। वे अस्पताल और औषधालय चलाते हैं, पानी की आपूर्ति का प्रबंधन करते हैं, जल निकासी व्यवस्था को बनाए रखते हैं, बाजारों के रखरखाव को सुनिश्चित करते हैं, पार्कों और पार्किंग स्थल का निर्माण और रखरखाव करते हैं, सड़कों और ओवर-ब्रिज के निर्माण और रखरखाव करते हैं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करते, स्ट्रीट लाइटिंग सुनिश्चित करते है, प्राथमिक विद्यालय चलाते हैं, संपत्ति और पेशेवर करों की वसूली करते है, टोल टैक्स संग्रह प्रणाली का संचालन करते है, श्मशान घाट का रखरखाव और जन्म एवं मृत्यु के रिकॉर्ड को बनाए रखते हैं।

पीपीआरसी रिपोर्ट जिसका शीर्षक 'दिल्ली टैंजिबल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट' है, ने दिल्ली के नगर निगमों द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों का विश्लेषण कर, उनके मूर्त परिणामों को रेखांकित किया। जमीनी स्तर के इस विश्लेषण ने न केवल शहर के विकास में नगर निगमों के योगदान को उजागर किया, बल्कि वर्षों से एमसीडी की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का भी दस्तावेजीकरण किया। साथ ही निगम अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों को भी तैयार करता है। इसलिए, सतत् सिद्धांतों के साथ सहभागी शासन अनिवार्य हो जाता है। यह कारण है कि 2017 में दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस दोनों को खारिज करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को वोट देकर पुनः विजयी बनाया। यह भाजपा के उन जन प्रतिनिधियों के अथक प्रयास ही थे, जिसके कारण भाजपा को चुनावों में दोबारा सफलता मिली। नगर निगम चुनाव के परिणाम 23 अप्रैल, 2017 को घोषित किए गए और भाजपा ने पिछले चुनावों की तुलना में 43 सीटें अधिक जीती। भाजपा की कुल सीटें 181 थी।

दिल्ली के नागरिक ने दिल्ली एमसीडी में आप पार्टी को खारिज कर दिया क्योंकि सत्ता में आने के कुछ महीनों के भीतर आप ने अपनी नैतिक चमक को खो दिया था। सुशासन का उसका वादा भी खोखला ही था क्योंकि आप सरकार के पास काम के नाम पर जनता को दिखाने दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। आप सरकार केवल केंद्र सरकार के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप का खेल खेलने और दिल्ली एमसीडी द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय लेने में व्यस्त थी।

स्वच्छ दिल्ली

स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। स्वच्छ वातावरण हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। दिल्ली नगर निगम जहां एक ओर 'सफाई मित्र' घर-घर भेजकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा दे रही है, वहीं 'स्वच्छ दिल्ली' को आकार देने के उद्देश्य से सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित कर रही हैं, अधिक संख्या में 'एफसीटीएस' का निर्माण कर रही हैं और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वैन की व्यवस्था कर रही है। गीले और सूखे कचरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में मानसिकता और व्यवहार में परिवर्तन लाने के प्रयास भी किए हैं और उन्हें 'सफाई मित्र' से संबोधित कर उनका सम्मान किया है। निगमों के इन प्रयासों से नागरिकों की मानसिकता और व्यवहार में भी बदलाव आया है। और यही स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य भी हैं, जिसको लेकर एक सकारात्मक साफ दिखता है।

लोक नीति शोध केन्द्र ने 'दिल्ली टैंजिबल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जहां हमने स्वच्छ दिल्ली के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र और फिक्स्ड कॉम्पेक्टर स्थापित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। स्वच्छ दिल्ली के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने और स्वच्छता के लिए 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' की योजना लागू की है।

दिल्ली में 'ढलाओ', हर इलाके में तीन दीवारों वाला कचरा संग्रहण स्थान है, लेकिन इस व्यवस्था में एक खतरा लगातार बना रहता है क्योंकि यदि कचरे के संग्रह में देरी होती है, तो सड़क पर कचरा फैलने का खतरा रहता है, जिससे स्वच्छता और बीमारी के प्रकोप का खतरा भी रहता है। इस मुद्दे पर ध्यान देते हुए दिल्ली के सभी नगर निगमों ने नियमित निगरानी से लेकर ढलाओं में 'शून्य अपशिष्ट समय' तय करने, घर-घर कचरा संग्रहण सेवा से लेकर कचरा एकत्र करने के लिए लगाए गए फिक्स्ड कॉम्पेक्टर्स की व्यवस्था को सुनिश्चित किया है। खाली क्षेत्रों को परिवर्तित किया जा रहा है और सृजनात्मक सुविधाओं के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 309 डंप हाउस थे जिनमें से 141 डंप हाउस बंद कर दिए गए हैं और खाली स्थलों का उपयोग सार्वजनिक रसोई, बुजुर्गों के बैठने की जगह और मनोरंजन केंद्र और अन्य सुविधाओं के रूप में किया जा रहा है। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली नगर निगम में कूड़े के निस्तारण के लिए 37 कॉम्पेक्टर प्लांट लगाए गए हैं। यह संयंत्र लगभग 7 टन कचरे को 1 टन कचरे में परिवर्तित करता है जिसे एसएलएफ साइट पर भेजा जाता है। अब घर-घर जाकर कचरा संग्रहण शुरू हो गया है, जिससे पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के करीब 45 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। सफाईकर्मियों के अथक प्रयासों से अब प्रतिदिन लगभग 2100 मीट्रिक टन कचरा एसएलएफ साइट पर पहुंचाया जा रहा है। पहले निगम ने गाजीपुर साइट पर भेजे जाने वाले कुल कचरे में 600 मीट्रिक टन प्रति दिन की कमी की है, जो कुल मिलाकर प्रति वर्ष 216,000 मीट्रिक टन है। बंद ट्रकों के माध्यम से कूड़ा-करकट ले जाया जाता है, जिससे कचरा अब सड़कों पर नहीं उड़ रहा है।

निर्माण कचरे के अवैध डंपिंग से निपटने के लिए एक नए दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास किया गया है, पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने निर्दिष्ट अधिसूचित स्थानों की संख्या को कम करने का निर्णय

चित्रः दक्षिण दिल्ली नगर निगम में घर-घर जाकर किया जा रहा संग्रहण

चित्रः दक्षिण दिल्ली नगर निगम में हो रही घरेलू खाद व्यवस्था

लिया है जहां मलबे को डंप किया जा सकता है। ऐसे स्थलों की संख्या 61 से घटकर मात्र 17 रह जाएगी।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के तहत प्रत्येक वार्ड में 533 ऑटो टिपर हैं। ई-टिप्पर व ई-रिक्शा, 819 हैंड रिक्शा, 29 लोडर प्रत्येक वार्ड में घर-घर जाकर कचरा संग्रहण व निस्तारण में लगे हैं। बड़े नालों की सफाई के लिए सुपर शेकर मशीन है, निगम दो सुपर शेकर मशीनों का उपयोग कर रहा है। साथ ही निगम की कॉलोनियों में स्थित छोटे नालों की सफाई के लिए निगम ने 28 सक्शन कम जेटिंग मशीनों को तैनात किया है। साथ ही निगम के पास 38 कम्पेक्टर मशीनें, 10 रोड स्वीपर, 2 सुपर सकर और 10 स्किड स्टीयर हैं।साथ ही निगम के अंतर्गत आने वाली कॉलोनियों में स्थित छोटे नालों की सफाई के लिए निगम 6 सक्शन कम जेटिंग मशीनों का उपयोग कर रहा है।

कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT) के तहत ईडीएमसी ने शाहदरा में झील का कायाकल्प किया है ताकि पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा सके जिसमें भोजनालयों, एक ओपन-एयर थिएटर और नौका विहार शामिल हैं।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने 143 ढालो घर को बंद कर दिया है और पश्चिम क्षेत्र में 29 वार्डों में 19 लाख की जनसंख्या के लिए दो फिक्स्ड कॉम्पेक्टर ट्रांसफर स्टेशन (FCTS) स्थापित किए हैं। इसके अलावा, नगर निगम ने अपने बजट 2020-21 में प्रत्येक क्षेत्र (प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन) में एक स्वच्छता केंद्र और सभी वार्डों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रह व्यवस्था की है। इसके अलावा, डोर-टू-डोर कचरा संग्रह और उसे एफसीटीएस तक ले जाने के लिए 7 टिपर नियुक्त किए गए हैं, साथ ही 2 तिपहिया वाहनों को बाजारों में दुकानों से कचरा संग्रह और एफसीटीएस तक ले जाने के लिए नियुक्त किया गया है। इसके अलावा एक कम्पेक्टर, हुक लोडर, टाटा 909 और टेम्पो, पार्कों से कचरा संग्रह के लिए एक सीएनजी कैंटर वाहन, साथ ही सड़कों पर फैले मालबा को हटाने के लिए जेसीबी और टिपर ट्रकों का प्रबंधन किया गया है। एक प्रगतिशील कदम उठाते हुए, एसडीएमसी ने ढलाओ को बदलने के लिए 6 नए एफसीटीएस के निर्माण का प्रस्ताव दिया है, जिसमें ए-2 ब्लॉक पंखा रोड के सामने, गैस गोदाम के पास, प्रो. जोगिंदर सिंह मार्ग शामिल है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए कदम उठाए हैं। निगम ने 6.5 सीयूएम क्षमता की 12 मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीनें, 4.5 कम क्षमता की 6 मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीनें, 8 केएल क्षमता की 10 सक्शन कम जेटिंग मशीन, 4 केएल क्षमता की 6 सक्शन कम जेटिंग मशीन, 2 सुपर सकर यूनिट और 15 स्किड स्टीयर लोडर लगाए हैं। इसके अलावा, निगम ने 4 कूड़े बीनने वाली मशीनें, 24 पानी के टैंकर 9 केएल क्षमता के साथ छिड़काव प्रणाली, 104 पानी के टैंकर 3 केएल क्षमता के साथ छिड़काव प्रणाली और 25 बैकहो लोडर खरीदे हैं।

चित्रः एनडीएमसी में ढालो घर

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत 550 'ढलाओ' हैं, जिनमें से 300 से अधिक को बंद कर दिया गया है और 97 कॉम्पेक्टर मशीनों को स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसमें से 81 को सफलतापूर्वक स्थापित किया जा चुका है। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण सेवा, कचरा एकत्र करने के लिए लगाए गए फिक्स कम्पेक्टर आदि के माध्यम से पूरी प्रक्रिया में तेजी लायी जा रही है। परियोजना के दूसरे चरण में फिक्स्ड कॉम्पेक्टर मशीनों को स्थापित करके खुले ढालओं को बंद करना शामिल है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने खाली साइटों को पुस्तकालयों और मिनी-गार्डन में परिवर्तित करना शुरू कर दिया है। वार्ड 57 में ऐसे ही एक ढलाओ को पुस्तकालय के तौर पर विकास किया गया है। वार्ड 53 में एक ढलाओ के आसपास की खाली जगह पर कलाकृतियां और फूल-पौधे लगाकर 'सेल्फी प्वाइंट' बनाया गया है, जबकि एक अन्य स्थल को वरिष्ठ नागरिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

साथ ही, उत्तरी दिल्ली नगर निगम 'स्वच्छ दिल्ली' बनाने के लिए बाढ़ के पानी को बाहर निकालने के लिए स्थापित 25 स्थायी पंपिंग स्टेशनों के संचालन और रखरखाव का काम देख रही है। इसलिए, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आरयूबी मुंडका और आरयूबी किशन गंज में 2 नए पंप हाउस स्थापित किए हैं और 25 स्थायी पंप हाउसों को नया रूप दिया है। इसके साथ ही निगम ने उन 162 पोर्टेबल पंपों को चालू कर दिया है, जो ऐसे स्थानों पर तैनात है जहां जलजमाव की संभावना थी।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम को दिसंबर, 2019 में ओडीएफ और जनवरी, 2022 में ओडीएफ+ प्रमाणित किया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में 301 सीटीसी, 129 पीटी और 1352 सार्वजनिक मूत्रालय हैं। सभी 301 सीटीसी को परिचालन और रखरखाव के लिए निजी एजेंसियों को आउटसोर्स किया गया है। निगम ने ओडीएफ+ और कचरा मुक्त शहर के बारे में जागरूकता के लिए दिसंबर 2021 महीने में एक कार्यशाला का आयोजन किया। साथ ही, निगम कचरा मुक्त शहर (3 स्टार) प्रमाणीकरण और ओडीएफ ++ प्रमाणीकरण के लिए आवेदन करने की योजना बना रहा है।

साथ ही, 8 एमआरएस, 104 टाटा एसीई, 6000 रोड साइड ट्विन बिन्स, 300 ट्राई-साइकिल रिक्शा, 700 प्रोक्योर्ड स्टेनलेस स्टील रोड साइड बिन्स 25 बैकहो लोडर, और 10-12 लीटर बिन्स क्षमता की आपूर्ति की गयी है। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए खरीदी गयी इन मशीनों पर कुल 32 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आरडब्ल्यूए, एमटीए और गैर सरकारी संगठनों के साथ विभिन्न बैठकें की हैं ताकि स्रोत पर कचरे को अलग करने के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके और "एकल उपयोग प्लास्टिक नहीं" को रोका जा सके। इसलिए, घरों के लिए 105 ऑटो टिपर, बाजार / शॉपिंग सेंटर के लिए 75 ऑटो टिपर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 15 मोबाइल कम्पेक्टर के साथ हुक लोडर के साथ 15 फिक्स्ड कम्पेक्टर तैनात किए गए हैं, और 8 रिफ्यूज कलेक्टर कम कॉम्पेक्टर भी तैनात किए गए हैं।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के अनुसार, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 1-3 लाख जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया। इस क्षेत्र को स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 रैंकिंग में इसके समकक्ष आबादी वाले 372 भारतीय शहरों में सबसे स्वच्छ घोषित किया है।

म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 के अनुसार उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 60 नगर पालिका निकायों में पहला स्थान हासिल किया है - यह सर्वेक्षण सेवा, योजना, वित्त, प्रौद्योगिकी और शासन के पांच मापदंडों पर नगर पालिकाओं के समग्र प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किए जाता है।

स्वच्छ भारत अभियान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत के लिए शुरू किया गया है। उन्होंने इस अभियान के तहत भारत के सभी शहरों और कस्बों को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा। इसे 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर लॉन्च किया गया था। यह कार्यक्रम लगभग सभी गांवों में स्वच्छता की समस्याओं को हल करने और कचरा प्रबंधन पर भी आधारित था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इसके अलावा, दिल्ली के सभी नगर निगमों ने बिजली, पानी और सफाई कर्मचारियों से लैस विश्व स्तरीय शौचालयों का निर्माण किया है। उदाहरण के लिए एसडीएमसी को 5 मई, 2018 को "खुले में शौच मुक्त" निगम क्षेत्र घोषित किया गया था और स्वच्छता ऐप लॉन्च किया गया था जिसके माध्यम से शिकायतों का समाधान 12 घंटे के भीतर किया जा रहा है। 396 सार्वजनिक शौचालय परिसरों और 129 सामुदायिक शौचालय परिसरों के निर्माण के लिए एसडीएमसी को अखिल भारतीय रैंकिंग में 11वां स्थान मिला है। इसके अलावा, आरसीसी, ईंट वर्क, फिनिशिंग वर्क, स्टील वर्क, एल्युमीनियम वर्क, सेनेटरी फिटिंग आदि द्वारा सभी मौजूदा टॉयलेट ब्लॉक्स और यूरिनल ब्लॉक्स की मरम्मत और रखरखाव किया जा रहा है, इसके अलावा टॉयलेट सीट, यूरिनल पॉट्स, पीवीसी टैंक, वाशबेसिन, टाइल वर्क, स्ट्रक्चरल स्टील कार्य को भी किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत ईडीएमसी ने महिलाओं के लिए 63 सामुदायिक और 290 सार्वजनिक शौचालयों और गुलाबी शौचालयों का निर्माण किया है। पूर्वी निगम के अंतर्गत सभी शौचालयों की धुलाई का कार्य 4000 लीटर क्षमता की 18 वाटर जेटिंग मशीन द्वारा किया जा रहा है।

शिक्षा

शिक्षा आधुनिक और प्रगतिशील समाज में मानव विकास का आधार है। यह वास्तव में एक राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास की नींव है। निस्संदेह, नीति निर्माताओं को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ावा देने के प्रयास करने चाहिए। यह सुनिश्चित करने के का प्रयास होना चाहिए हैं कि सभी सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों के बच्चे ऐसे नीतिगत उपायों से समान रूप से लाभान्वित हों। हालांकि, शिक्षा क्षेत्र गतिशील है और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा समर्पित प्रयासों की आवश्यकता है कि नीतियों का उचित कार्यान्वयन किया जाए। दिल्ली की आप सरकार के कार्यकाल के दौरान राजधानी में शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाने के दावों के मामले को परखा जाना आवश्यक है और तथ्यों एवं आंकड़ों के परिपेक्षय में इन दावों की सत्यता का पता लगाना अवश्यक है।

शिक्षा की गुणवत्ता की पहचान करने के कई महत्वपूर्ण कारक है जो छात्रों को सीखने और विकसित होने के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करने के लिए एकजुट किये जाते है और जो अंततः एक प्रगतिशील समाज के निर्माता बनते है। इन कारकों के दो महत्वपूर्ण पहलुओं है - जिनकों भौतिक और मानव बुनियादी ढांचे के संदर्भ में समझा जा सकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए दो कारक अपरिहार्य हैं और किसी भी कीमत पर इनसे समझौता नहीं किया जा सकता है। यह खंड इन दो मापदंडों पर दिल्ली सरकार के स्कूलों की स्थिति को चित्रित करता है और यह समझने का प्रयास करता है कि वे शिक्षा और छात्रों के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। दिल्ली सरकार के स्कूलों और दिल्ली एनसीटी में एमसीडी स्कूलों में स्कूल के बुनियादी ढांचे के तुलनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से भी इस समझ को मजबूत किया जा सकता है। इस खंड में यह मूल्यांकन सीखने को प्रभावित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं और परिणाम पर आधारित हमारे निष्कर्षों पर तैयार किया गया है।

भौतिक मूलढ़ांचा

स्कूल की इमारतें, कक्षाएं, प्रयोगशालाएं और उपकरण-शिक्षा का बुनियादी ढांचा है - स्कूलों में सीखने के माहौल के मूलभूत तत्व हैं। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि उच्च-गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा बेहतर प्रदर्शन की सुविधा देता है, इसके माध्यम से छात्र परिणामों में सुधार कर सकते है और अन्य लाभों के साथ ड्रॉपआउट दरों को कम किया जा सकता है।

चिंता की बात यह है कि दिल्ली सरकार के स्कूल इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर पिछड़ते जा रहे हैं। हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की ढांचागत क्षमताओं का आकलन करने के लिए उनकी स्थिति का गहन विश्लेषण किया। हमारे सर्वेक्षण ने शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक कुछ सबसे बुनियादी सुविधाओं के संबंध में महत्वपूर्ण कमियों का खुलासा किया। स्कूलों और आंकड़ों दोनों को एकत्र किए गए और कुछ निम्नलिखित तथ्य हैं जो निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं। यह विश्लेषण एमसीडी और राज्य सरकार के स्कूलों की तुलना करता है। यह तुलनात्मक अध्ययन इस बात की बेहतर समझ को भी सामने लाता हैं कि कैसे सक्रिय प्रशासनिक, नीति नियंत्रण और निर्णय लेने से शिक्षा की गुणवत्ता और परिणाम छात्रों के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं।

हालांकि, आगे के शोध से पता चलता है कि आप सरकार के तहत 25 नए स्कूलों में से कोई भी निर्माण नया नहीं है। ये सभी स्कूल निर्माण 2015 से पहले यानी आप सरकार के सत्ता में आने से पहले ही शुरू हो चुके थे। सदन के पटल पर सरकार के उत्तर का उल्लेख करते हुए, हम पाते हैं कि आज कुल 82 भूखंड खाली हैं जहां नए स्कूलों का निर्माण किया जाना चाहिए था। उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार के पास 2015 से इन 82 भूखंडों का कब्जा था और उनमें से किसी पर भी निर्माण शुरू नहीं किया गया है। इसके बावजूद, दिल्ली सरकार इस बात पर जोर देती रहती है कि नए स्कूलों के निर्माण के लिए साइटों की कमी एक बाधा है। यह तथ्य स्पष्ट रूप से शिक्षा क्षेत्र की बुनियादी आवश्यकताओं के प्रति उदासीनता का संकेत देते हैं।

ईडीएमसी 354 निगम विद्यालय और 11 निगम सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय चला रहा है जिसमें लगभग 1.65 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं और बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। ईडीएमसी स्कूल नंद नगरी ए-4, नंद नगरी बी-4, न्यू कोंडली बी-ब्लॉक, शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र में निगम स्कूल, और त्रिलोकपुरी ब्लॉक -6 स्कूल के भवन का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना की गई है ताकि बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की जा सकें। साथ ही, ईडीएमसी ने अधिक संख्या में स्कूल बनाने की योजना बनाई है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षित किया जा सके। इसलिए निगम ने शाहदरा दक्षिण अंचल में 6 विद्यालय भवन जबकि विजया मोहल्ला में एक विद्यालय और शाहदरा उत्तर क्षेत्र में 7 विद्यालय का निर्माण कार्य शुरू किया है। साथ ही विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

निगम ने छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को भी नियुक्त किया है, इस प्रकार, ईडीएमसी ने अब तक 1315 शिक्षकों की भर्ती की है। साथ ही 19.04.2021 तक संविदा आधार

सुसज्जित तरीके से बनाए रखा भौतिक बुनियादी ढांचे के साथ एमसीडी स्कूल की तस्वीरें

पर कार्यरत शिक्षकों को 31.03.2022 तक अनुबंध विस्तार से लाभान्वित किया गया है। निगम ने बच्चों के लिए आकस्मिक मृत्यु, चोट, अंग हानि आदि के संबंध में 'बीमा योजना' भी लागू की है। इस योजना के तहत, उपरोक्त स्थिति के मामले में छात्रों के परिवारों को 25000 से 50000 तक की सहायता प्रदान की जा रही है।

इसके अलावा, छात्रों और अभिभावकों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निगम केंद्र सरकार के 'स्कूल चलो मिशन' को उत्साहपूर्वक लागू कर रहा है और छात्रों के बीच वस्तुओं का वितरण भी कर रहा है।

निगम ने वर्ष 2020-21 में छात्रों को वर्दी के लिए 19.78 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है। निगम के प्रत्येक वार्ड के विद्यालय की तीन कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है और अब तक 3,68,01,601 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि के साथ 125 स्मार्ट बोर्ड लगाये जा चुके हैं । ईडीएमसी निगम विद्यालय में अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था, कुल 124 विद्यालय भवनों में अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की गयी है। ईडीएमसी के तहत आने वाले 6 निजी स्कूलों को मान्यता प्रदान की।

कुल 5889 बड़े और 4371 छोटे आकार के डेस्क खरीद कर पूर्वी निगम के विद्यालयों को आपूर्ति की जा चुकी है। और पहली बार नर्सरी के बच्चों के बैठने की व्यवस्था के लिए कुल 13248 प्लास्टिक मोल्डेड कुर्सियां और 2208 प्लास्टिक टेबल खरीदे गए हैं।

सत्र 2020-21 में रामनगर में एकल पाली का विद्यालय फिर से खोल दिया गया है जो वर्ष 2010 में बंद कर दिया गया था।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 30 उत्कृष्ट विद्यालय हैं जहां सभी छात्रों को स्मार्ट बोर्ड और स्मार्ट कक्षाओं की सुविधा मिल रही है, 185 प्रतिभा विद्यालय, पिछले पांच वर्षों में निर्मित 40 नए स्कूल भवन में 702 नए कक्षाएं, 190 नए शौचालय, 62 शौचालय ब्लॉक की सुविधा प्रदान की गई है। हर स्कूल में विकलांग छात्रों के लिए स्कूलों में 649 प्रिंटर और स्कैनर, 440 नए हैंड वॉश स्टेशन, 110 स्मार्ट क्लासरूम, 129 सीसीटीवी कैमरे, 163 सोलर सिस्टम, 515 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आदि उपलब्ध कराए गए हैं। निगम ने प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में यूनिफॉर्म की राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी है।

छात्रों को बेहतर शिक्षा सुविधा प्रदान करने के लिए निगम ने 2017 से 326 शिक्षकों को काम पर रखा और 40 पीटीएम आयोजित की हैं। इसके साथ ही, दक्षिण दिल्ली नगर निगम 582 स्कूलों का संचालन कर रहा है जिसमें 14 नर्सरी स्कूल भी शामिल हैं। निगम ने 662 शिक्षकों की भर्ती की है और 581 स्कूलों में मेगा पीटीएम आयोजित की है।

स्वच्छता और सुविधाएं

2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण था। शौचालय और इसके बुनियादी ढांचे की कमी के कारण किशोर लड़कियों में स्कूल छोड़ने की दर और अनुपस्थिति की उच्च संख्या थी। लड़कियों ने विशेष रूप से युवावस्था में पहुंचने के बाद स्कूलों को छोड़ना

नजफगढ़ में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तस्वीरें। स्कूल न सिर्फ जर्जर हालत में है बल्कि बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा करता है

शुरू कर दिया क्योंकि उनके पास 'उपयोग करने योग्य' शौचालय या पानी की कमी थी। शौचालय के बुनियादी ढांचे की कमी को देखते के कारण ड्रॉपआउट दर और अनुपस्थिति के लिए प्रमुख मुद्दा बन गया था, पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान शुरू किया। इसने देश के सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय के साथ शौचालय होना अनिवार्य कर दिया और एक साल के भीतर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस राष्ट्रीय मिशन में कॉर्पोरेट समर्थन जुटाने के लिए गहनता से काम किया। पहल के शुभारंभ के समय, सभी सरकारी स्कूलों में कार्यात्मक शौचालयों की उपलब्धता में अंतर का आकलन किया गया था और यह सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन के आधार पर हस्तक्षेप विकसित किए गए थे कि प्रत्येक बच्चे को लिंग के आधार पर अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो। एक वर्ष की अवधि में पूरे भारत में 2,61,400 स्कूलों में 4,17,796 शौचालयों का निर्माण किया गया। स्कूलों में बच्चों का नामांकन और प्रतिधारण, विशेष रूप से लड़कियों के मामले में वृद्धि हुई है। 'स्वच्छ विद्यालय' को भी 2016 के प्रधान मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी। हालांकि, दिल्ली में कहानी बिल्कुल अलग है। बहुत से लोग मानते हैं कि आप सरकार ने शिक्षा पर ध्यान दिया। हालांकि, इस कहानी का एक बहुत ही शर्मनाक पक्ष भी है।

दिल्ली सरकार स्वच्छ भारत कोष से एक भी शौचालय का निर्माण करने में विफल रही। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार 40.31 करोड़ रुपये होने के बावजूद स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक भी शौचालय का निर्माण करने में विफल रही। दिल्ली सरकार 'उपयोग योग्य' शौचालय प्रदान करने में विफल रही और कुछ मामलों में दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शौचालयों का निर्माण भी नहीं लिया गया। दिल्ली सरकार, अपने लेखांकन कौशल के आधार पर शिक्षा के लिए बजट के अपने उच्च आवंटन को लेकर दावा करती रही। लेकिन इसका स्याह पक्ष यह है कि इन निधियों का उपयोग तक नहीं किया गया है। इसलिए, कोई आश्चर्य नहीं कि सरकार स्कूलों में नए शौचालयों का निर्माण करने में विफल रही।

दिल्ली सरकार शौचालयों में पानी की तो बात ही छोड़िए, स्कूलों में शौचालय का बुनियादी ढांचा मुहैया कराने में विफल रही है। दिल्ली सरकार अन्य स्कूलों की अनदेखी करते हुए सिर्फ अपने 50 मॉडल स्कूलों पर ध्यान केंद्रीत किये हुए है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली सरकार के बड़े-बड़े वादों के बावजूद, उनके स्कूलों में पीने का पानी, साफ शौचालय नहीं है। जहां कम से कम शौचालय बने हैं, वहां शौचालयों में पानी नहीं है, खासकर लड़कियों के लिए सुविधाएं न के बराबर है। इसके अलावा, पानी की टंकियां बहुत खराब अवस्था में थीं। स्कूलों ने दिल्ली सरकार को लिखा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दिल्ली के स्कूलों की बदहाली बताती है कि कैसे आप सरकार ने स्कूलों की बुनियादी जरूरतों की उपेक्षा की है। स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को दिन भर पानी के बिना रहना पड़ता है। स्कूल में लंबे समय से पानी नहीं होने के कारण छात्राओं को जमीन पर

एमसीडी स्कूलों में शौचालय और पेयजल की सुविधा

ही पेशाब करना पड़ रहा है।

स्वच्छ पेयजल

दिल्ली के स्कूलों में न केवल शौचालय के बुनियादी ढांचे की कमी है, बल्कि बुनियादी आवश्यकताओं की भी कमी है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली के केवल 5% सरकारी स्कूल बुनियादी ढांचे के मामले में आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

शिक्षा का अधिकार कानून द्वारा अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुसार कई स्कूलों में पीने के साफ पानी के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। स्कूलों में टंकियों की नियमित रूप से सफाई नहीं की जाती है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। कुछ स्कूलों में उपलब्ध पानी गंदा और अस्वच्छ होता है जिससे छात्र दस्त जैसी विभिन्न बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा, पानी को फिल्टर करने के लिए कोई आरओ प्लांट नहीं है और पानी से बदबू आती है।

पानी की कमी के अलावा, उपलब्ध पानी की मात्रा भी एक समस्या है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के स्कूलों में उपलब्ध खराब सुविधाओं को लेकर दिल्ली सरकार की खिंचाई की। पूर्वोत्तर दिल्ली के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पर्याप्त शिक्षकों, पीने के पानी और शौचालयों की कमी है, मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों में कहा गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर के एक पूर्ण सहायता प्राप्त सरकारी स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर दिल्ली सरकार की खिंचाई की। स्कूल पहले एक सोसायटी द्वारा चलाया जाता था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। स्कूल में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था और स्कूल में खेल के मैदान के लिए निर्धारित भूमि का उपयोग घरेलू और अन्य कचरे को डंप करने के लिए किया जा रहा था।

स्मार्ट क्लासेस

स्मार्ट क्लासरूम तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन्नत क्लासरूम हैं। स्मार्ट क्लासरूम की अवधारणा शिक्षण की पारंपरिक पद्धति को पूरी तरह से खत्म नहीं करती है, बल्कि यह पारंपरिक तरीकों के साथ प्रौद्योगिकी के उपयोग को पूरक बनाने का प्रयास करती है। शिक्षण के लिए संवादात्मक उपकरणों का उपयोग करने का चलन रहा है। दुनिया भर में उभरती प्रवृत्ति निर्देशों के व्यक्तिगत तरीकों पर जोर देने के साथ सीखने के अधिक व्यक्तिगत और लचीले रूपों को विकसित करने की वकालत करती है। इन तकनीकों के उपयोग के साथ, कक्षा में शिक्षण "ब्लैकबोर्ड और चॉक" मोड से "कंप्यूटर और प्रोजेक्शन" मोड में बदल जाती है। स्मार्ट क्लासरुप में स्मार्ट बोर्ड, दस्तावेज़ कैमरा, लैपटॉप कंप्यूटर, दस्तावेज़ कैमरा और ऐसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग शामिल है जो छात्रों को एक इंटरैक्टिव लर्निंग में मदद करते हैं। सहस्राब्दी वह पीढ़ी है जो डिजिटल तकनीक और इंटरनेट की उपस्थिति में बढ़ रही है, और उनके पास पिछली पीढ़ी के शिक्षार्थियों से बहुत अलग सुविधाएं हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न अध्ययनों से संकेत मिलता है कि मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षण एक प्रभावी तरीका है। यह छात्रों में अवधारणा के बारे में दीर्घकालिक स्मृति पैदा करता है। ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म दुनिया भर के छात्रों को सामान्य शिक्षाशास्त्र के माध्यम से सीखने के लिए मंच प्रदान करते हैं। 'दिल्ली टैंजिबल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट' रिपोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा स्तर पर वीसैट का उपयोग करके आभासी कक्षा की प्रतिकृति की

एमसीडी स्कूलों में व्यक्तित्व विकास की पहल

आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, जिसे तब मुंबई में सफलतापूर्वक लागू किया गया था।

कई निजी स्कूलों ने इस तकनीक को अपने वैश्विक शिक्षण पद्धति के हिस्से के रूप में बहुत पहले आरंभ किया था। पिछले एक दशक में सरकारी स्कूलों के छात्रों को निजी स्कूल के छात्रों के समान सीखने में सक्षम बनाने के लिए कक्षाओं में मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म के महत्व को समझते हुए और वैश्विक शिक्षा पाठ्यक्रम के अनुरुप सरकार ने कक्षा को स्मार्टबोर्ड और गैजेट्स से सुसज्जित किया है। 2019 तक, ईएमसीडी के तहत पांच स्कूल थे जो स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करते थे। कोविड-19 महामारी के दौरान ईएमसीडी ने छात्रों के लिए वर्कशीट और होमवर्क के वितरण के लिए डिजिटल कक्षाओं का संचालन करने के लिए 'गूगल मीट' प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया।

स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए 128 स्मार्ट बोर्ड लगाए गए हैं। निगम ने स्मार्ट क्लास शुरू की है, स्कूल भवन में सुधार किया है और छात्रों के लिए पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराया है। ईडीएमसी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या 2,15,000 है और उनके माता-पिता या अभिभावकों को मेगा पीटीएम के माध्यम से जोड़ा गया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 4 स्कूल स्थापित किए हैं और 4 अन्य बनाने की प्रक्रिया में है।

25 जनवरी 2022 को ईडीएमसी ने ऑनलाइन शिक्षण के लिए शिक्षकों द्वारा विकसित 'ई-लाइब्रेरी' लॉन्च किया है। पोर्टल में 354 ईडीएमसी स्कूल शामिल हैं, जिससे 4500 शिक्षकों और 2.25 लाख से अधिक छात्रों को लाभ होगा।

दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने भी 581 स्कूलों में मेगा पीटीएम आयोजित किया है और विभिन्न मुद्दों से संबंधित चुनौतियों और निवारण के बारे में चर्चा की है। इसके साथ ही निगम प्रत्येक वार्ड में एक ऐसा स्मार्ट स्कूल बनाने की महत्वाकांक्षी योजना को क्रियान्वित कर रहा है जो अंकगणित विज्ञान या रोबोटिक्स पर आधारित ज्ञान प्रदान कर सके।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर निजी और एमसीडी स्कूलों में 'गोद लेने की योजना' को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम सकारात्मक तरीके से उठाए हैं। साथ ही, महामारी के दौरान एनडीएमसी ने ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से छात्रों के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। निगम ने मेंटर शिक्षकों की टीमों द्वारा सामग्री विकसित की गई थी। सामग्री को 30 सप्ताह में विभाजित किया गया था और छात्रों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए वीडियो तैयार किए गए थे। साथ ही मेंटर शिक्षकों की टीमों द्वारा नैतिक मूल्यों पर आधारित 80 जीवन कौशल और गतिविधियों वाली वर्कशीट तैयार की जा रही है। साथ ही ऑफलाइन जुड़े छात्रों के लिए ऑफलाइन वर्कशीट का प्रावधान भी सुनिश्चित किया जा रहा है। छात्रों शिक्षा में स्कूलों का बंद होना कोई बाधा नहीं थी।

इसके अलावा उत्तरी दिल्ली नगर निगम एक भारत—श्रेष्ठ भारत के तहत अमृत महोत्सव के 75 वर्ष कार्यक्रम के तहत पर्यावरण के प्रति जागरुकता फैला रहा है और विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से जेंडर संवेदीकरण जैसे समसामयिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रीत कर रहा है। साथ ही, निगम के मेंटर्स द्वारा 'गुमनाम नायकोन की शौर्य गाथा' नाम की एक किताब तैयार की गई है। इसमें 75 बहादुर नायकों की कहानियां शामिल हैं। पुस्तक की विशेषता यह है कि प्रत्येक पृष्ठ पर एक क्यूआर कोड दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक छात्र वीडियो के माध्यम से हमारे नायकों के बारे में जान सके।

नवाचार

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगाना तो नाम मात्र

एमसीडी स्कूलों में 'बाला' तकनीक के तहत कक्षा कक्षों के बाहर ज़ेबरा क्रॉसिंग और अन्य पहल

का काम है। अभी तक हमें जो आरटीआई डेटा मिला है, उसके मुताबिक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सिर्फ 10 फीसदी में ही स्मार्ट क्लास हैं। कुछ स्कूलों ने यह भी माना है कि सभी स्मार्ट क्लासेस कार्यात्मक भी नहीं हैं। उदाहरण के लिए जोन 27 और जोन 28 में कुल मिलाकर 8 स्मार्ट क्लास है जिनमें से केवल 4 ही चालू स्थिति में हैं। जिससे संकेत मिलता है कि सरकार छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा रही है लेकिन यह सुनिश्चित नहीं कर रही है कि छात्रों को नीति से लाभ मिल रहा है या नहीं।

इसके अलावा, हम दिल्ली भर के एमसीडी स्कूलों में सकारात्मक रुझान पाते हैं। गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा एक मजबूत नींव के निर्माण के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है और नगर निगम शासन के तहत स्कूलों में दिए गए संसाधनों इसमें एक सराहनीय काम कर रहे हैं।

विज्ञान क्लब

स्कूलों में सभी वर्गों के बच्चों के लिए एक विज्ञान क्लब है। इस तरह के क्लब छात्रों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए नवाचार और आविष्कार को प्रोत्साहित करते हैं। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर बच्चों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देना है। सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में हमने कई स्कूलों का दौरा किया गया था, जिसमें छात्रों को मॉडलिंग और व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से चीजों को बनाने और बुनियादी अवधारणाओं को समझने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए योग्य शिक्षकों के साथ विज्ञान कक्ष थे। उनके पास विज्ञान मॉडल की एक श्रृंखला थी, अपशिष्ट मॉडल से तैयार विज्ञान मॉडल, पर्यावरण के अनुकूल समाधान विकसित करना आदि शामिल था।

स्कूलों ने स्वयंसेवी संगठनों के साथ भी करार किया है, जिनका उद्देश्य छात्रों को कैरियर मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करना और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। संगठन प्रतिभाशाली छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान चयन समिति चलाता है और उनके कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करता है।

यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मजबूत नींव बनाने और युवा मन में वैज्ञानिक सोच पैदा करने के बाद छात्रों को अपनी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कम अवसर मिलते हैं। कुछ स्कूलों में साइंस स्ट्रीम के साथ, छात्रों को अपनी रुचि विकसित करने और माध्यमिक शिक्षा में अपनी जिज्ञासा को खिलाने के लिए अवसर नहीं मिलता है और अंततः दिल्ली सरकार के स्कूलों में सीनियर सेकेंडरी में साइंस स्ट्रीम का विकल्प चुनते हैं। देखा जाए तो जहां एक ओर निगम के छात्रों को सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और वहीं दिल्ली सरकार के स्कूलों में बच्चों को सीखने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है।

स्वास्थ्य

रोग निवारण उपाय

मॉनसून का मौसम और लगातार बारिश मच्छरों के लार्वा के प्रजनन के लिए अनुकूल हैं जो डेंगू और मलेरिया का कारण बनती हैं। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों के मामलों की संख्या को कम करने के लिए नगर निगम ने नियमित धुंआ करने, एंटी-लार्वा दवाओं के छिड़काव सहित एक 'गहन अभियान' शुरू किया। घरेलू सर्वेक्षण, हैंडबिल और स्टिकर के माध्यम से जागरूकता अभियान, धुंआ करने और एंटी-लार्वा दवाओं के छिड़काव के माध्यम से मच्छरों के प्रजनन को रोकने में लगभग 2,000 श्रमिकों को शामिल किया गया है। इस अभियान में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के प्रतिनिधियों के साथ वार्ड स्तर की बैठकें और पहले चरण में पर्चे का वितरण शामिल है। दूसरे चरण में मछली को जलाशयों में छोड़ा गया ताकि वे लार्वा को रोका जा सके और तीसरे चरण में बड़े नालों में मच्छर रोधी दवाओं का छिड़काव किया गया।

गौरतलब है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने सड़कों पर कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए 2 और ट्रक खरीदे हैं। एक विशेष अभियान में ईडीएमसी ने एक नाव द्वारा यमुना नदी के आसपास के क्षेत्रों में कीटनाशक का छिड़काव किया क्योंकि इन क्षेत्रों तक पहुंचना मुश्किल है। निगम ने दिल्ली में वेक्टर जनित रोगों के मामलों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक का छिड़काव भी किया है।

साथ ही दीपावली और छठ पूजा उत्सव के दौरान वेक्टर रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए घरों, स्कूलों या सार्वजनिक स्थानों की छतों की जांच के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान निगम ने प्रत्येक वार्ड में जागरूकता शिविर लगाकर 'डेंगू माह' का आयोजन किया। प्रत्येक वार्ड में फॉगिंग मशीन भी बढ़ाकर 2 कर दी गई है। साथ ही नगर निकाय ने सफाई विभाग में कचरा संग्रहण में लगे 70 ड्राइवर, 100 बेलदार और 6 जेटिंग मशीन तैनात की है। ईडीएमसी ने डेंगू से बचाव के लिए घर-घर जाकर कीटनाशकों के छिड़काव की प्रक्रिया को अंजाम दिया। ट्रेन के माध्यम से रेलवे ट्रैक के चारों ओर कीटनाशकों का छिड़काव भी किया गया और जहां कहीं पहुंचना संभव नहीं था, वहां ड्रोन मशीनों के माध्यम से कीटनाशकों का छिड़काव किया गया। हर घर में ओआरएस के पैकेट भी बांटे गए। 2021 में एमसीडी ने जेजे कॉलोनियों में लगभग 42,000 घरों की जांच की, जिनमें से लगभग 800 घरों में मच्छरों के लार्वा पाए गए और 24 जुलाई तक शहर में डेंगू के 48 मामले सामने आए।

इसके अलावा, मलेरिया के निदान के लिए जांच के लिए, ईडीएमसी ने पूर्वी दिल्ली के विभिन्न मलेरिया क्लीनिकों के लिए अनुबंध के आधार पर 3 सेवानिवृत्त मलेरिया निरीक्षकों की नियुक्ति की है।

डेंगू के खिलाफ घरेलू मच्छर प्रजनन चेकर्स मुख्य रूप से 35 स्थलों पर तैनात किये गये हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने ऐसे दस्ते की तैनाती की, जो प्रत्येक शनिवार को हर इमारत और साइट का दौरा करती है। टीम ने 29,672 परिसरों का दौरा किया है और दोषियों के खिलाफ नोटिस भी जारी किये।

निगम के अस्पतालों में करीब 250 अतिरिक्त बेड जोड़े गये हैं, इसी के साथ फीवर क्लीनिक में कुल 191500 मामले आये। 2017-19 के बीच चिकनगुनिया के 33, डेंगू के 1732 और मलेरिया के 765 पॉजिटिव व्यक्तियों का इलाज किया गया है। साथ ही, जनता में वेक्टर जनित जागरूकता के लिए मेगाफोन / लाउडस्पीकर, पोस्टर, हैंड बिल, स्टिकर के माध्यम से जनता को जागरूक किया जा रहा है। जबकि, मुनादी और बल्क एसएमएस के माध्यम से वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही, सभी स्वास्थ्य केन्द्र पर जनता के लिए तीन दिवसीय सामूहिक जांच शिविर और उनकों शिक्षित करने का काम किया गया,

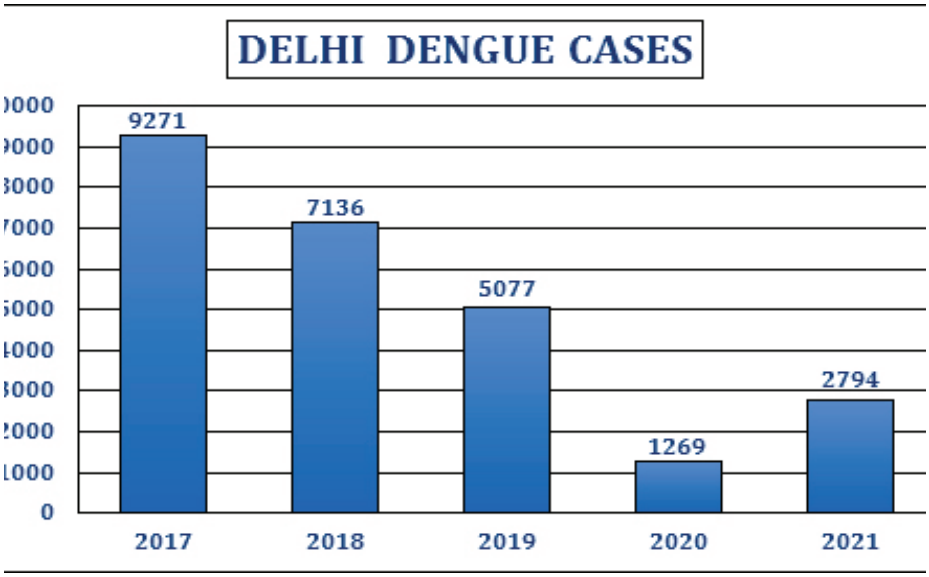

इसके लिए गांधी जयंती और विश्व मधुमेह दिवस को चुना गया। नगर निकायों द्वारा किए गए उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप 2017 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी में दर्ज डेंगू के मामलों में 69.86% की भारी गिरावट आई है। जैसा कि ग्राफ से स्पष्ट है कि दक्षिण, उत्तर और पूर्व दिल्ली नगर निगमों की अथक पहल के परिणामस्वरूप मामलों में भारी गिरावट आयी है। साथ ही केंद्र सरकार के दूरदर्शी कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत नगर निगमों ने ने अब तक 14,97,113 टीकाकरण किए हैं, जो नागरिकों को बीमारियों से लड़ने और बिमारीयों की संख्या में कमी लाने में प्रमुख भूमिका निभाता हैं।

आयुष स्वास्थ्य सेवा

आयुष उन चिकित्सा प्रणालियों का संक्षिप्त नाम है जो भारत में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी में प्रचलित हैं। ये प्रणालियां निश्चित चिकित्सा दर्शन पर आधारित हैं और बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की स्थापित अवधारणाओं के साथ स्वस्थ जीवन जीने के तरीके का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत की केंद्र सरकार और दिल्ली के नगर निगमों के संयुक्त प्रयासों से कार्यरत या स्वीकृत औषधालयों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय राजधानी ने वर्ष 2019 में 87 नई औषधालयों को कार्यरत औषधालयों की सूची में शामिल किया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम 114 औषधालयों का संचालन कर रहा है।

साथ ही, ईडीएमसी ने विनोद नगर के आयुर्वेदिक औषधालय का जीर्णोद्धार किया है और आयुष प्रणाली के तहत आने वाली दवाओं और आवश्यक उपकरणों को उपलब्ध करवाया है। जबकि, एसडीएमसी 35 औषधालयों, 3 पंचकर्म अस्पतालों और 2 आयुर्वेदिक मधुमेह केंद्र के माध्यम से नागरिकों को आयुष चिकित्सा प्रणाली के तहत मुफ्त सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रत्येक औषधालय में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कोविड -19 महामारी से बचाव के लिए निगम ने लॉकडाउन के समय 1.5 लाख नागरिकों के बीच रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं का वितरण किया। आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार के लिए विभाग द्वारा प्रत्येक अंचल में जन-जागरण शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों को कोविड-19 महामारी के प्रति जागरूक किया गया।

दक्षिण दिल्ली नगर निगम घरेलू उपचार और निकटतम उपलब्ध संसाधनों की जानकारी प्रदान करने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित कर रहा है। इसके अलावा, निगम कई नए औषधालयों, अस्पतालों, पंचकर्म केंद्रों, होम्योपैथिक औषधालयों का निर्माण कर रहा है और यहां तक कि पुराने औषधालयों और अस्पतालों का रखरखाव भी कर रहा है।

आधुनिक चिकित्सा के अलावा उत्तरी दिल्ली नगर निगम दिल्ली में अपना पहला आयुष अस्पताल खोलने के लिए पूरी तरह तैयार है। अस्पताल सरोजनी नगर इलाके में बनेगा। इस अस्पताल में सभी सुविधाएं जैसे आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा उपलब्ध होंगी।

आयुष के तहत यहां चिकित्सा पद्धतियां तैयार की जाएंगी। जहां अस्पताल का निर्माण होना है, वहां पुनर्विकास का काम चल रहा है। अस्पताल के लिए मेट्रो स्टेशन और सरोजनी नगर बाजार के अलावा सीजीएचएस कॉम्प्लेक्स के पास करीब 30,000 वर्ग फुट जगह चिन्हित की गई है। करीब तीन साल तक अस्पताल की देखभाल आयुष मंत्रालय करेगा। इसके बाद इसे एनडीएमसी को सौंप दिया जाएगा। यदि कोई शुल्क रखा भी जाता है तो वह 50 रुपये से लेकर अधिकतम 300 रुपये तक होगा। सभी चिकित्सा पद्धतियों की अलग-अलग ओपीडी बनाई जाएंगी और लोग हर जगह नियमित रूप से अपनी बीमारियों का इलाज करा सकेंगे। इन पांच विधियों के तहत चिकित्सा के लिए अलग-अलग चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे जैसे आयुर्वेद में पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा में हाइड्रो, और एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर आदि।

कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व समय में, लोगों का विश्वास प्रतिरक्षा बूस्टर और उपचारात्मक उपचार के रूप में आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली के प्रति अत्यधिक बढ़ रहा है।

चित्रः शंकर गार्डन में औषधालय

अन्य स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं

- दिल्ली के तीन नगर निगम 6 सामान्य अस्पताल, पांच कॉलोनी अस्पताल, 23 पॉलीक्लिनिक और सैकड़ों औषधालय, प्रसूति एवं बाल कल्याण केंद्र चलाते हैं, जहां रोजाना 1 करोड़ से अधिक मरीज आते हैं।
- पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत 7 प्रसूति गृह हैं जिनमें कुल 107 बिस्तरों की सुविधा है। यह केंद्र संस्थागत प्रसव और बाल देखभाल सेवाएं प्रदान करते हैं। 23 एम एंड सीडब्ल्यू केंद्र हैं जो पूर्वी दिल्ली की वंचित आबादी के एक बड़े हिस्से को आउटरीच सेवाएं प्रदान करते हैं। इसी तरह, दक्षिण दिल्ली नगर निगमों के तहत 2018-2019 में मातृत्व घरों में लगभग 2500 सुरक्षित और सामान्य प्रसव हुए हैं, जिसमें शून्य मातृ मृत्यु दर के साथ-साथ लगभग 67000 महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गई है। उत्तरी दिल्ली नगर निगमों में शून्य मातृ मृत्यु दर के साथ 2018-2019 में मातृत्व घरों में लगभग 2500 सुरक्षित और सामान्य प्रसव हुए।
- ईडीएमसी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल के बुनियादी ढांचे में सुधार और उन्नयन किया है, जिसमें ओपीडी ब्लॉक की क्षतिग्रस्त छत की मरम्मत, आइसोलेशन वार्ड की मरम्मत, क्षतिग्रस्त ओवरहेड टैंकों और सैनिटरी पाइपों की मरम्मत, इंजीनियरिंग विभाग के आवश्यक कमरों में सुधार शामिल है। जिसमें 40 लाख रुपये की लागत आयी है।
- शाहदरा चेस्ट क्लिनिक में सीआर सिस्टम के साथ एक्स-रे मशीन की स्थापना के लिए एक अलग कमरे के निर्माण सहित भवनों का उन्नयन किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत 2.42 लाख रुपये है।
- ईडीएमसी द्वारा एनआरएचएम के तहत 07 प्रसूति गृहों के लिए रोगी कल्याण समिति के लिए 2 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
- स्वामी दयानंद अस्पताल में ईडीएमसी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहा है और क्षमता को बढ़ाकर 370 बेड, 250 वार्ड, 120 एम एंड सीडब्ल्यू ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा, सभी प्रमुख विशिष्टताओं के साथ 6 उच्च स्तरीय निर्भरता इकाई (एचडीयू) बिस्तर भी उपलब्ध हैं।
- निगम के तहत जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी नागरिक केंद्रित सेवा ऑनलाइन उपलब्ध है, उदाहरण के लिए जन्म और मृत्यु (आरबीडी) का पंजीकरण, साथ ही नाम जोड़ने और सुधार जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
- दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने ओडीएफ++ (खुले में शौच मुक्त) का दर्जा हासिल किया है, साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वेक्षण 2021 कार्यक्रम के अंतर्गत अपने चार क्षेत्रों में 191 नए सार्वजनिक शौचालयों की शुरुआत की है।
- उत्तर दिल्ली नगर निगम ने एमएचए पोर्टल पर विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस के अनुदान/नवीकरण की शर्तों को लेकर 3 वर्ष का विस्तार किया है और स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस नीति को सरल बनाया है।
- उत्तर दिल्ली नगर निगम ने खाद्य संबंधित वस्तुओं की बिक्री और खरीद के लिए एक ई-कार्ट नीति शुरू की है। साथ ही पानी की ट्रॉली की फीस भी 1000 रुपये से घटाकर 200 रुपये कर दी गई है।
- इसके अलावा 1 कॉलोनी अस्पताल, 17 पॉलीक्लिनिक, 6 प्रसूति गृह, 31 औषधालय, 11 मोबाइल वैन, 59 प्रसूति और बाल कल्याण केंद्र, 1 पीयूएचसी, 1 वीडी क्लिनिक, 6 एम एंड सीडब्ल्यू क्षेत्रीय इकाइयां उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत हैं। इन संस्थानों में लगभग 3104 बिस्तर हैं और समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को सभी स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त प्रदान की जाती हैं।
- उत्तरी दिल्ली नगर निगम की प्रयोगशालाओं ने 2017 में 1.34 लाख एक्स-रे और 83000 अल्ट्रासाउंड सहित 67.92 लाख से अधिक परीक्षण किए हैं जो वर्तमान में बढ़कर 42.42 लाख परीक्षण हो गए हैं। साथ ही अब तक 27000 सर्जरी और 21000 डिलीवरी की जा चुकी हैं। इन स्वास्थ्य इकाइयों में 50,000 से अधिक बच्चों को प्राथमिक टीके लगाए गए हैं।
- 64 डॉक्टर, 16 फार्मासिस्ट, 36 स्टाफ नर्स और 116 एएनएम नियमित स्टाफ इन सुविधाओं का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज में 65 नई नियुक्तियां की गईं। 2019 में 245 छात्रों और 45 इंटर्न को उत्तरी दिल्ली मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया गया था।
- निगम द्वारा हिंदू राव और कस्तूरबा अस्पतालों में एक कैंसर क्लिनिक का उद्घाटन किया गया, जहां सभी जैव रासायनिक और रेडियोलॉजिकल जांच मुफ्त प्रदान की जाएगी।
- स्तन कैंसर का जल्द पता लगाने के लिए रेडियोलॉजी विभाग में मैमोग्राफी मशीन लगाई गई है।
- सभी संस्थानों में ईडब्ल्यूएस लागू किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप एमबीबीएस में सीटों की संख्या 50 से

बढ़ाकर 60 हो गई है।

- नेफ्रोलॉजी विभाग को नई दो डायलिसिस मशीनों के साथ अपग्रेड किया गया है और यूरोलॉजी विभाग को फ्लेक्सिबल सिस्टोनेफ्रोफिब्रेस्कोप के साथ पूरी तरह से अपग्रेड किया गया है जो एचआरएच में निदान और चिकित्सीय प्रक्रियाओं में मदद करता है।
- मेडिकल कॉलेज में अकादमिक प्रदर्शन उच्चतम गुणवत्ता का बना हुआ है और एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज के पहले बैच (एमबीबीएस 2013) के 22 छात्रों ने एनईईटी परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटें में दाखिला पाया।
- एचआरएच और केएच में नर्सिंग स्कूल को 22 सीटों के साथ अपग्रेड किया गया है।
- गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्पतालों में 800 एमए, 600 एमए और 500 एमए एक्स-रे मशीन, इमेजिंग के साथ स्लिट लैंप, 2डी इकोकार्डियोग्राफी आदि सहित नए उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

हरित दिल्ली

अनादि काल से दिल्ली पर्यावरणविदों के लिए एक पसंदीदा स्थान और एकांत प्रेमियों के लिए स्वर्ग रहा है। आज भी, जब पूरा शहर आधुनिकता की लय को स्पंदित करता है, तो आप नीम और जामुन पेड़ों के नीचे कुछ शांत क्षेत्रों को आसानी से देख सकते हैं। दिल्ली अपने बगीचे और हरे भरे स्थानों, बेहतर आय के अवसरों से लोगों को आकर्षित करती है। दिल्ली के इस तेजी से विकास के परिणामस्वरूप बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव पड़ा है और सभी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसका सामना करते हुए दिल्ली नगर निगम ने कई पहल की हैं और आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ग्रीन पर्यटन के लिए सबसे उपयुक्त स्थनों में से एक है।

हरित आवरण को बनाए रखने, प्रदूषण को कम करने और अपने निवासियों, विशेष रूप से बच्चों को हरित पार्क और आधुनिक सुसज्जित खेल क्षेत्र प्रदान करने के लिए तीनों नगर निगमों ने अभिनव प्रयास किए हैं। पूर्वी दिल्ली को हरा-भरा रखने और पौधों की देखभाल के लिए "एक पेड़ को अपनाओ" कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत नागरिक स्वेच्छा से पेड़ अपनाकर इसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। पेड़ों को गोद लेने वाले नागरिकों के लिए ट्री गार्ड पर नाम और पता बार लगाया जाएगा। वर्तमान में नागरिकों द्वारा कुल 4880 वृक्षों को गोद लिया गया है।

चित्रः एनडीएमसी द्वारा किया गया पार्कों का सौंदर्यीकरण

पहले निगम के पास ऊंचे पेड़ों की छंटाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए नगर विकास कोष से लगभग 27 लाख रुपये में दो हाइड्रोलिक ट्री-प्रूनर मशीनें खरीदी गई हैं, ताकि ऊंचे पेड़ों को अब सुविधाजनक तरीके से संवारा जा सके।

2012-13 में, लोक नीति शोध केंद्र ने बच्चों के साथ-साथ युवाओं के लिए पार्कों में अधिक सुविधाओं की आवश्यकता का संकेत दिया। हमने भौतिक गतिविधियों में नागरिकों की रुचि पैदा करने के लिए पार्कों और खुले स्थानों के सौंदर्यीकरण के कदमों पर भी अधिक जोर दिया है।

इस प्रकार, 2016 में तीन नगर निगमों ने पहले पार्क में ओपन जिम स्थापित किया और स्क्रैप सामग्री का उपयोग करते हुए बच्चों के पार्कों की स्थापना की, जिसे नागरिकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली, यहां तक कि पहले व्यायाम उपकरण या जिम सदस्यता लेने में असमर्थ वर्गों की खुशी अब बढ़ गयी है। जिस तरह से इन पार्कों की अवधारणा की गई है, प्रत्येक पर बुनियादी उपकरण और साइनबोर्ड के साथ उनके उपयोग पर निर्देश देते हुए, उससे नए लोगों के लिए सुविधाओं का उपयोग करना आसान और सुरक्षित हो रहा है।

लोगों को स्वस्थ गतिविधियों में शामिल करने के अलावा, जिमों को पार्कों में अपराध दर को कम करने में मदद मिली है क्योंकि पार्क में अधिक लोग आते हैं, जो अन्यथा ज्यादातर नशा करने वालों और असामाजिक तत्वों द्वारा उपयोग किए जाते थे। ओपन जिम की लोकप्रियता ने संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों को उनके लिए अपने स्थानीय क्षेत्र के विकास निधि का एक बड़ा प्रतिशत आवंटित करने के लिए प्रेरित किया है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम की ओर से रचनात्मक पहल करते हुए कबाड़ सामग्री से बने एक पुराने ट्रक पर मोबाइल चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है, जिस पर छोटे बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं। इस

चित्रः ईडीएमसी द्वारा किया गया पार्कों का सौंदर्यीकरण

दिशा में निगम ने पार्कों में बैठने के लिए लकड़ी के 40 बेंच और स्टैंड बनाकर गिरे हुए पेड़ों का सदुपयोग किया है। वहीं वेस्ट टू आर्ट प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न पार्कों में 110 पुरानी व टूटी हुई लोहे की बेंचों की मरम्मत कर उन्हें स्थापित किया गया, जिससे करीब एक करोड़ रुपये की बचत हुई है। वहीं 7.50 लाख रुपये खर्च कर पार्कों की सुंदरता को बढ़ाया। यह पहल उन लोगों के लाभ को ध्यान में रखकर की गई है जिनके घर के पास कोई पार्क नहीं है। इसके अलावा, प्रत्येक वार्ड के एक पार्क में एक्यूप्रेशर टाइलें लगाई जा रही हैं ताकि बुजुर्गों और शुगर के रोगियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और प्रत्येक क्षेत्र के पार्कों में ओपन-एयर जिम की व्यवस्था की गई है।
वर्तमान में ईडीएमसी 2162 पार्कों की देखभाल कर रहा है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 903 एकड़ है। लगभग 1025 सजावटी पार्क, 8 हर्बल पार्क, 148 चिल्ड्रन पार्क आदि हैं। इसके अलावा, ईडीएमसी डीडीए के 70 पार्कों को संभाल रहा है और 28 पार्कों के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसके तहत कंपनियों को मुफ्त में जगह उपलब्ध कराई जाएगी। पीपीपी मॉडल के आधार पर, ईडीएमसी ने 92 पार्कों और 4 फ्लाईओवर के लिए निजी कंपनियों के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया है। इस सहयोग से सार्वजनिक स्थानों पर रखरखाव, सौंदर्यीकरण और ऐसी ही अन्य सुविधाओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। पार्कों की सुंदरता बढ़ाने के लिए निगम ने पेड़ों पर एनिमल लाइक फेस मास्क लगाए हैं। साथ ही 20 पार्कों में वाटर हार्वेस्टिंग लगा दिया गया है, इसके अलावा कुल 30 पार्कों का पुनर्विकास कर रिफ्रैब्रिकेट किया गया है।
इसके अलावा, ईडीएमसी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी चेस्ट अस्पताल में 125 केवी पीएनजी जेनरेटर स्थापित किया है जो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुपालन है, जिस पर 23 लाख रुपये की लागत आयी है। अब तक, निगम ने 17,741 पेड़ और 34,717 जड़ी-बूटियां और झाड़ियां लगाई हैं और 4813 से अधिक ट्री गार्ड लगाए गए हैं। 26 हरित अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र हैं जहां विभिन्न नर्सरी और पार्कों में खाद बनाई जा रही है, वहां 110 जाल लगाए गए हैं। इसके अलावा, निगम ने प्रदूषण को रोकने के लिए और कदम उठाए हैं जिसमें सबसे प्रमुख 8000 लीटर क्षमता की 40 वाटर स्प्रिंकलर मशीन की स्थापना है जो प्रतिदिन 650 किलोमीटर सड़क पर छिड़काव, धूल के कणों की सफाई, धूल झाड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। विशेष रूप से ईडीएमसी ने उद्यान पर्यटन महोत्सव, 2021 में भाग लिया और विभिन्न श्रेणियों में 5 पुरस्कार जीते।
दक्षिण दिल्ली नगर निगम 6102 पार्कों की देखभाल कर रहा है और 120 खंबो पर वर्टिकल गार्डन लगाया है, साथ ही 1 लाख पेड़ और 1.5 लाख हरी झाड़ियां लगाई हैं। सौंदर्यीकरण के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया है। प्रदूषण के स्तर को और कम करने के लिए नगरपालिका ने 75 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं और 123 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं, जिससे प्रति वर्ष 1.65 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है और प्रदूषण में भी कमी हो रही है।
एसडीएमसी ने 197 पार्कों में झूले लगाए हैं, 103 पार्कों में काम चल रहा है, 1 चिल्ड्रन पार्क (नंदन वन) तैयार किया गया है और इसके तहत 5 अन्य स्थानों की पहचान की गई है जिसमें नए और आधुनिक झूले, विभिन्न आकर्षक कलाकृतियां, गेट, प्ले स्टेशन, ट्री डेक आदि लगाये जाने है। 243 ओपन जिम स्थापित किए गए, और 57 पर काम चल रहा है। 37 फिटनेस ट्रेल पार्कों का निर्माण जिसमें 3 तरह के एक्यूप्रेशर ट्रैक पर हल्के, मध्यम और भारी व्यायाम होंगे। इसके अलावा, ग्राम सभा भूमि पर पार्क बनाने का कार्य प्रगति पर है। एसडीएमसी ने 494 पार्कों में स्प्रिंकल इरीगेशन सिस्टम के माध्यम से सिंचाई के लिए व्यवस्था की है जिसके परिणामस्वरूप 50% पानी की बचत हुई है। पार्क में चारदीवारी, ग्रिल, प्रवेश द्वार, बेंच, हाई मास्ट लाइट, कच्चे और पक्के वॉकिंग ट्रैकों का निर्माण और नवीनीकरण द्वारा पार्कों का सौंदर्यीकरण किया गया। सभी पार्कों में पौधरोपण किया गया। साथ ही, कई डीडीए पार्क जो दयनीय स्थिति में थे, उनका निगम द्वारा सौंदर्यीकरण किया गया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में नगर निगम के 478 स्कूलों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए हैं।
इसके अलावा, एसडीएमसी ओपन जिम के अपग्रेड वर्जन के तौर पर वॉकिंग ट्रैक्स और लाइट, मीडियम और हैवी एक्सरसाइज के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है।

प्रदूषण मुक्त दाह संस्कार

सदियों पुरानी हिंदू परंपरा, अंत्येष्टि, या मृतकों के लिए अंतिम संस्कार, परिवार और मित्रों द्वारा नदी या जलाशय के पास किया जाने वाला संस्कार है और जिसमें शव को लकड़ी की चिता पर रखकर जलाया जाता है। बाद में, राख को गंगा या अन्य नदियों में विसर्जित कर दिया जाता है। दाह संस्कार से पहले किए गए अनुष्ठानों के लिए उपयोग किए जाने वाले फूल, कलश और अन्य सामान बाद में राख और हड्डियों के साथ नदी में फेंक दिए जाते हैं। 2016 में आईआईटी कानपुर द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, यह बताया गया गया था कि 4% जहरीले कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन को श्मशान स्थलों के माध्यम से हवा में छोड़ा जाता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 2,129 किलोग्राम से अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड, 33 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, 346 किलोग्राम पीएम 10, और दाह संस्कार से प्रतिदिन 312 किग्रा PM2.5 धूल के कण उत्सर्जित हो रहे थे।

प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने गाजीपुर और कड़कड़डूमा श्मशान में 4 सीएनजी-आधारित श्मशान घाट स्थापित किए हैं, जिसकी अनुमानित लागत रु 1.25 करोड़ रुपये है। साथ ही निगम चिता के लिए लकड़ी की जगह पराली और गाय के गोबर का इस्तेमाल कर रहा है। यह पहल लकड़ी को बचाने में मदद करती है और चिता की पारंपरिक विधि की तुलना में लगभग 90% कम प्रदूषण पैदा करती है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अपने सुभाष नगर और ग्रीन पार्क श्मशान घाट में अंतिम संस्कार करने के लिए अधिक जगह बनाने के लिए सीएनजी भट्टियां स्थापित की हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने श्मशान घाटों के लिए एक वास्तविक समय निगरानी प्रणाली और केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब, दिल्ली में 32 कोविड श्मशान और कब्रिस्तान हैं, जो एक साथ प्रतिदिन 1,100-1,200 शवों को संभालने की क्षमता रखते हैं। इनकों लगभग 1,500 मामलों को संभालने की क्षमता के साथ विकसित किया जा रहा है। श्मशान घाटों का आधुनिकीकरण भी किया गया है जिसमें प्लेटफार्मों और सीएनजी सुविधाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। (संदर्भ बजट 2020-21)

दिल्ली में प्रदूषण मुक्त दाह संस्कार में समस्या उन लोगों के रवैये से है जो परंपरा के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर संबंधित परिवार के सदस्य पहले से ही आघात में होते हैं और वह पर्यावरण की रक्षा जैसे विषयो पर विचार नहीं करना चाहाते है। पर्यावरण के अनुकूल दाह संस्कार का विकल्प चुनते समय, उनके रिश्तेदारों द्वारा उनकी आलोचना की जाती है। एक अन्य विकल्प प्रदान किया जा रहा है जो पारंपरिक चिता का एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें पारंपरिक तरीके की तुलना में लगभग दो क्विंटल कम लकड़ी की आवश्यकता होती है। इसकी कीमत लगभग 1,200 रुपये है और लकड़ी और शव को जलाने में लगभग दो घंटे लगते हैं।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने ऑनलाइन प्रार्थना प्रणाली प्रदान करना शुरू कर दिया है और सभी नगर श्मशान घाटों पर ई-श्मशान पर्ची भी जारी करना शुरू कर दिया है। निगम ने वजीरपुर श्मशान घाट पर एक ग्रीन श्मशान, निगम बोध घाट पर प्रतिदिन 36 शवों की अंतिम संस्कार क्षमता के साथ 6 सीएनजी भट्टियां स्थापित की हैं, और श्मशान के लिए गाय के गोबर या पराली के उपयोग की शुरुआत की है। इसके अलावा, निगम द्वारा किए गए प्रयासों के कारण अब निगम बोध घाट पर मोक्षदाह में पारंपरिक लकड़ी आधारित दाह संस्कार में 50 प्रतिशत की कमी देखी गयी है।

दाह संस्कार के लिए जगह बढ़ाने और पारंपरिक चिता से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के प्रबंधन से लेकर एमसीडी ने इस संबंध में कई पहल की हैं। दिल्ली में पहली बार ग्रीन श्मशान की व्यवस्था शुरू की गई है। इसके अलावा, मोक्षदा जैसे अंतिम संस्कार करने के लिए अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं। इन उपायों से न केवल खतरनाक उत्सर्जन में कमी आती है बल्कि दाह संस्कार की लागत और जलाऊ लकड़ी की खपत में भी कमी आती है।

चित्रः ग्रीन पार्क में सीएनजी आधारित शवदाह गृह का निर्माण

लैंडफिल साइटों का भार कम किया गया

कचरे के बढ़ते ढेर के अलावा लैंडफिल साइट के साथ मुख्य समस्या विषाक्त पदार्थ और ग्रीनहाउस गैसें हैं। लैंडफिल कचरे को उपयोग में लाने और उनकी ऊंचाई कम करने के लिए नगर निगम प्लास्टिक कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में कर रहे हैं। इसके अलावा औद्योगिक और अन्य कचरे से वंडर पार्क भी बनाया गया है। आम जनता द्वारा कम मात्रा में मालबा को इन स्थलों पर डंप किया जा सकता है, जहां से इसे रीसाइक्लिंग प्लांट द्वारा सी एंड डी अपशिष्ट पुनर्चक्रण संयंत्र में ले जाया जाता है। बल्क जेनरेटर को सीएंडडी वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी या सैनिटरी लैंडफिल साइट पर मलबा डंप करने का निर्देश दिया गया है। उदाहरण के लिए, उत्तरी दिल्ली नगर निगम में बल्क जनरेटरों को या तो सी एंड डी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा जहांगीरपुर, बुराड़ी के पास या भलस्वा एसएलएफ साइट पर मलबा डंप करने के लिए निर्देशित किया गया है।

सी एंड डी अपशिष्ट संयंत्र की स्थापना 8 लाख टन से अधिक सी एंड डी कचरे को संसाधित करने की क्षमता के साथ की गई है। इसके अलावा, ईडीएमसी ने 60 साइटों का सीमांकन किया है जहां से वे सी एंड डी कचरा एकत्र कर रहे हैं। अब तक 8.8 लाख टन सी एंड डी कचरे को संसाधित किया जा चुका है।

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अपशिष्ट-वार शहरों द्वारा-उत्पन्न सी एंड डी कचरे को चैनलाइज़ करने के लिए नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2021 में सर्वोत्तम अभ्यास, एनडीएमसी ने आईएल एंड एफएस एनवायरनमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईईआईएसएल) परियोजना की क्षमता को बढ़ाया है - यहा देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है - जो निर्माण और विध्वंस कचरे को रीसायकल करने के लिए निजी-सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर आधारित है, यह परियोजना दिल्ली के बुराड़ी इलाके में स्थित है। संयंत्र वैज्ञानिक रूप से 2,000 टन प्रति दिन (टीपीडी) सीएंडडी कचरे को समुच्चय में संसाधित करता है जिसे तैयार-मिक्स कंक्रीट, सीमेंट ईंटों आदि में परिवर्तित किया जाता है। संयंत्र से 16 लाख से अधिक पुनर्नवीनीकरण कंक्रीट ब्लॉकों का उपयोग सुप्रीम कोर्ट के नए अनुबंध भवन में किया जा रहा है। संयंत्र ने 2009 में अपनी स्थापना के बाद से 45 लाख टन से अधिक सीएंडडी कचरे को संसाधित किया है जो अन्यथा यमुना नदी या अन्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध रूप से डंप किया जाता। सुप्रीम कोर्ट के नए भवन और एमपी फ्लैटों के निर्माण में लगभग 23 लाख टन पुनर्नवीनीकरण सामग्री का उपयोग किया गया। डीडीए द्वारा बनाई गई 4 किमी एक्सप्रेस

चित्रः एसडीएमसी में वेस्ट टू वंडर आर्टिफैक्ट

बक्करवाला रोड में 2.6 लाख टन पुनर्नवीनीकरण सी एंड डी सामग्री का उपयोग किया गया था।

ईडीएमसी ने कचरे को हरित ऊर्जा में उपयोग करने के लिए एनटीपीसी के साथ एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए। साथ ही, ईडीएमसी ने एक 8 मेगावाट का संयंत्र स्थापित किया है और इसे 11 मेगावाट के संयंत्र तक विस्तारित करने के लिए काम कर रहा है। 16 संयंत्र स्थापित किए गए हैं जिनमें से 14 कचरे को उर्वरक में परिवर्तित करते हैं और 2 संयंत्र कचरे को बिजली में परिवर्तित करते हैं। इसके अलावा, निगम पहले की तुलना में गाजीपुर साइट पर भेजे जा रहे कुल कचरे को 600 मीट्रिक टन प्रति दिन कम कर दिया है, जो संचयी रूप से प्रति वर्ष 216,000 मीट्रिक टन है। एसडीएमसी में प्रतिदिन 40 टन गीले कचरे से कम्पोस्ट बनाने के लिए 4 मशीनें खरीदी गई हैं, प्रतिदिन 5 टन ठोस कचरे से खाद बनाने के लिए चार प्लांट लगाए जाएंगे। इसके अलावा, एसडीएमसी प्रतिदिन 1 टन ठोस कचरे से खाद बनाने के लिए 4 संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है और प्रत्येक वार्ड में

खाद के गड्ढे बनाए जा रहे हैं। 15 टन खराब / अनुपयोगी सामग्री से 30 कलाकृतियां बनाकर अपशिष्ट स्थलों का सौंदर्यीकरण, मुनिरका में लगभग 8 एकड़ में रॉक गार्डन, खिडकी एक्सटेंशन में लगभग 3 एकड़ में जामुन पार्क का सौंदर्यीकरण किया गया है, जो देखते ही बनता है। अपशिष्ट सामग्री का उपयोग करके पिछले कई वर्षों से 12 फ्लाईओवर के नीचे सौंदर्यीकरण किया गया है, अब एसडीएमसी के इस प्रयासों की सराहना की जा रही है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने भलस्वा डंपसाइट पर 28 ट्रोमेल्स और 4 क्लेमैन मशीनों को स्थापित करके पुराने कचरे का उपचार किया है और 80 लाख मीट्रिक टन में से 20.30 लाख मीट्रिक टन (25.30%) कचरे को साफ किया है। इससे डंपसाइट की ऊंचाई और क्षेत्र में कमी आई है। इसके तहत 11 मीटर ऊंचे पहले टीले को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है और दूसरे टीले की सफाई का कार्य प्रगति पर है।

एसडीएमसी मलबे से टाइल आदि बनाने के लिए दो सी एंड डी अपशिष्ट रीसाइक्लिंग प्लांट स्थापित कर रहा है, जिससे निर्माण कचरे को पुनर्नवीनीकरण किया जाएगा। निगम क्षेत्र से निकलने वाले पूरे ठोस कचरे से बिजली पैदा करने के लिए एक और प्लांट लगाया जा रहा है।

जैविक कचरे से खाद बनाने के लिए एसडीएमसी ने 8 चिपर-कम-श्रेडर मशीनें खरीदी हैं, 2 और खरीदी जाएंगी, 301 वर्मी कम्पोस्ट बेड तैयार किये गये हैं, 100 अन्य बेड कम्पोस्ट बनाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। नगर निगम द्वारा प्रतिदिन 120 क्विंटल जैविक कचरे का प्रसंस्करण किया जाता है। इसके अलावा, निगम ने ओखला में 2000 मीट्रिक टन का ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है, जिसमें कुल 3200 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट और 2000 मीट्रिक टन गीला अपशिष्ट का उपचार किया जा सकता है।

उत्तर निगम वर्ष 2009 से बुराड़ी के पास जहांगीरपुर में एक सी एंड डी अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र चला रहा है। संयंत्र की प्रारंभिक क्षमता 500 एमटी/दिन थी जिसे बाद में वर्ष 2014 में सी एंड डी अपशिष्ट के बढ़ते प्रवाह को पूरा करने के लिए 2000 एमटी/दिन तक बढ़ा दिया गया था। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 20 दिसंबर, 2021 से पीपीपी मोड पर रानीखेड़ा में न्यूनतम क्षमता 1000 टीपीडी का अपना दूसरा सी एंड डी अपशिष्ट पुनर्चक्रण संयंत्र स्थापित किया है।

सीएसपी, करोल बाग और नरेला जोन से एकत्र किए गए 2200 एमटी–2500 एमटी कचरे को भलस्वा लैंडफिल साइट पर डंप किया गया है। इसी प्रकार, उत्तर दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में 2500 मीट्रिक टन एमएसडब्ल्यू के प्रसंस्करण द्वारा ऊर्जा सुविधाओं के लिए एकीकृत अपशिष्ट स्थापित करने के लिए निगम और आईओसीएल के बीच 19/01/2021 को एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया है और निविदा प्राप्त हुई है। यह प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। एक आईओसीएल के माध्यम से 31.12.2022 तक एकीकृत अपशिष्ट से ऊर्जा सुविधाओं के संचालन का आश्वासन दिया गया है। 20 लाख टन कचरे का पहले ही जैव खनन किया जा चुका है और 15 एकड़ और 11 मीट्रिक टन कचरा अभी शेष है। अभी तक बायोमाइनिंग से कई क्षेत्रों को पूरी तरह से साफ किया जा चुका है। एनएचएआई, एनटीपीसी, आई एंड एफसी, डीडीए, डीएम (उत्तर) और डीएम (एन-डब्ल्यू) के साथ अन्य प्रक्रियाओं को लेकर संवाद कामय किया गया है।

ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए दिल्ली में एमसीडी द्वारा की गई पहल सतह, वायु और भूजल पर प्रदूषण को कम करने और शहर में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करती है। ये परियोजनाएं कचरा प्रबंधन की समस्या को दूर करने में मदद कर रही हैं। एमसीडी की ये पहल और नीतियां हमारी राजधानी के "हरित क्षेत्र" होने की परिकल्पना को साकार कर रही है।

स्वच्छ ऊर्जा

अक्षय ऊर्जा हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। यह सुरक्षित और हरित एवं किफायती विकल्प है। इसके अलावा, यह ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के रूप में कार्य करता है। नतीजतन, इससे प्रदूषण नहीं होता है। इस प्रकार, दिल्ली नगर निगम विभिन्न योजनाओं और पहलों को लागू करते हुए सौर ऊर्जा के अधिक से अधिक उपयोग को बढ़ावा दे रहा है।

दिल्ली निगमों ने सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया और अपने सभी स्कूलों और भवनों पर सौर पैनल स्थापित किए। सौर ऊर्जा से उत्पन्न अधिशेष बिजली बीएसईएस को उपलब्ध कराई गई, जिससे निगम ने 3.72 करोड़ रुपये की राशि अर्जित की। (संदर्भ बजट 2020-21)

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 1,77,015 लाख एलईडी लाइटें लगाई हैं। इसके अलावा, एनडीएमसी ने 164 स्कूल साइटों पर कुल 1170 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्रों को सफलतापूर्वक स्थापित किया है जिसमें रोहिणी, नरेला, केशव पुरम, सिविल लाइंस जैसे अन्य स्थान शामिल हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत एनडीएमसी ने चार व्यापक क्षेत्रों यानी ई-गवर्नेंस और एम-गवर्नेंस, सूचना प्रसार, बिजली वितरण और सौर ऊर्जा में 1897.27 करोड़ की 69 परियोजनाओं की कल्पना की थी। 69 परियोजनाओं में से 33 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है और 36 परियोजनाओं में काम प्रगति पर है। साथ ही निगम ने 200 सरकारी स्कूलों में

चित्रः नजफगढ़ क्षेत्र में स्थापित एलईडी स्ट्रीट लाइट और सोलर पैनल

सोलर प्लांट लगाए थे। इन सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना पर कुल खर्च लगभग 3.53 करोड़ रुपये है। जनवरी, 2022 तक, इन सौर संयंत्रों पर दर्ज कुल सौर ऊर्जा उत्पादन 10.55 लाख यूनिट से अधिक है।

2017-2021 के दौरान, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ऑटो विभाग, ईडीएमसी ने पारंपरिक लाइटों को एलईडी लाइटों से बदला और कुल 1.77 लाख लाइटों को इस माध्यम से बदला गया। इस प्रकार, प्रति वर्ष औसत ऊर्जा बचत 9 करोड़ यूनिट तक पहुंच गयी और कार्बन फुटप्रिंट में भी कमी आयी है। विशेष रूप से, वित्तीय दृष्टि से परियोजना का परिणाम प्रति वर्ष लगभग 45 करोड़ की बचत है। इसके अलावा, इस परियोजना ने ऊर्जा संरक्षण 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एनईसीए 2020)' में भारत का सर्वोच्च 'मेरिट का प्रमाण पत्र' पुरस्कार प्राप्त किया, इसके साथ ही निगम को सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए 'हुडको (एमओएचयूए, भारत सरकार के तहत) पुरस्कार मिला है।

डार्क स्पॉट की पहचान और उनको कम करने के लिए निगम द्वारा एक गैर सरकारी संगठन 'सेफ्टीपिन' के साथ करार किया गया। जिसके तहत एक सर्वेक्षण किया गया और रिपोर्ट का अनुपालन करते हुए वर्ष 2018 में 3225 स्ट्रीट लाइट पोल और 6065 स्ट्रीट लाइट्स को डार्क स्पॉट पर स्थापित किया गया।

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन के समझौते के अनुरूप 208 भवनों की छतों और खुली जगहों पर सोलर पैनल लगाया गया, जिससे न सिर्फ निगम का बिजली बिल पर खर्च 87 करोड़ रुपये की कमी आयी, निगम की आय भी बढ़ी है। इसके अलावा, दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने 2 लाख सोडियम-आधारित स्ट्रीट लैंप को एलईडी लाइट्स और जीआईएस-आधारित स्ट्रीट लाइटों से बदल दिया है और 2.25 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों को चालू किया है। साथ ही नजफगढ़ जोन में 20 मेगावाट बिजली बनाने की भी योजना है। स्ट्रीट लाइट की बेहतरी के लिए निगम ने निम्न कदम उठाए हैंः-

- डार्क स्पॉट की पहचान के बाद पोल और एलईडी लाइट्स की स्थापना
- 35W एलईडी लाइट्स के साथ 5 मीटर पर 158 जीआई पोल
- डबल 30W फ्लड लाइट के साथ 6mtr पर 19 MS पोल
- सभी मंदिरों और गुरुद्वारे के सामने पोल और एलईडी लाइट की स्थापना
- 5 नए सार्वजनिक शौचालयों का विद्युतीकरण।
- 140W फ्लड लाइट के साथ जिला केंद्रों की रोशनी
- एसडीएमसी कम्युनिटी हॉल में 36 वाट की एलईडी एलईडी लाइटें लगाईं
- जिला केन्द्र पर पुलिस सम्मान केन्द्र की रौशनी
- रामलीला/कृष्णलीला/छठ और दुर्गा पूजा में अस्थाई रोशनी
- 3 एफसीटीएस का विद्युतीकरण
- सभी पार्कों में 108 हाई मास्ट और एलईडी लाइट के खंभों की स्थापना
- पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर 1,16,000 स्ट्रीट लाइटें थीं जिन्हें एलईडी लाइटों से बदल दिया गया है जिससे 78% ऊर्जा बचाने में मदद मिली है। साथ ही, उन्होंने अपने शिकायत निवारण में सुधार किया है, अब तक निगम स्ट्रीट लाइट से संबंधित समस्याओं को 2 से 24 घंटे के भीतर हल कर रहा है।

नागरिक केंद्रित शासन

किसी सरकारी विभाग या एजेंसी में हमारे बिलों का भुगतान करने के लिए लंबी लाइनों में खड़े होना और डेस्क पर कर्मचारी की उदासीनता शहर के अधिकांश निवासियों के लिए एक परिचित अनुभव है। लेकिन कुछ शहरों से अच्छी खबर है कि कैसे ई-गवर्नेंस या शहरी प्रशासन में आईटी के उपयोग से शहरी भारत में सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी पर फर्क पड़ रहा है।

दिल्ली नगर निगमों की विभिन्न सेवाएं जैसे संपत्ति कर का भुगतान, व्यापार लाइसेंस, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य सेवाएं अब एक क्लिक पर उपलब्ध है। उदाहरण के लिए अब प्रमाणीकरण और लाइसेंस जारी करने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि नागरिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संबंधित विवरण दर्ज कर सकते है और संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापन के बाद स्वीकृत दस्तावेजों को डाउनलोड कर सकते हैं।

इन सेवाओं को शहर भर में 3,000 से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर भी उपलब्ध कराया गया है, जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार की एक पहल है।

एसडीएमसी द्वारा स्कूलों में 28 आधार पंजीकरण केंद्र शुरू किए गए हैं और नागरिक सुविधाओं की निगरानी और जनता की शिकायतों के निवारण के लिए 311 मोबाइल ऐप लॉन्च हुए हैं। इसके अतिरिक्त आवासीय एवं औद्योगिक भवनों के मानचित्रों की स्वीकृति हेतु एकल खिड़की अनुमोदन प्रणाली का निर्माण किया गया, जिसके फलस्वरूप अब इसके लिए 9 विभिन्न एजेंसियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी है, जिससे रिश्वतखोरी और दलाली पर रोक लगेगी।

इसके अलावा, ईडीएमसी के आधिकारिक पेज पर कुल 23 ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं जिनमें आवश्यक सेवाएं जैसे कोविड हेल्पलाइन पोर्टल/कॉल सेंटर, लाइसेंस और लीज प्रबंधन, डिजिटल संग्रह, पालतू कुत्ते का पंजीकरण आदि शामिल हैं। जबकि, उत्तरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली नगर निगमों इनके साथ क्रमशः कुल 46 और 42 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, ईडीएमसी ने उद्योगों के लिए एक ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली शुरू करने की योजना की घोषणा की है।

दिल्ली के नगर निगमों को विभिन्न परियोजनों के अंतर्गत केंद्र सरकार से धन प्राप्त होता है जिसके चलते अब कई लंबे समय से अटकी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए एनएमसीडी के तहत लंबे समय से लंबित रानी झांसी फ्लाईओवर का उद्घाटन अक्टूबर 2018 में किया गया था, जिसकी कल्पना 1998 में की गई थी और 2006 में दिल्ली के तत्कालीन एकीकृत नगर निगम द्वारा कमीशन किया गया था। देखा जाए तो मूल रूप से सेंट स्टीफेंस अस्पताल से फिल्मिस्तान सिनेमा तक बनने वाले इस 1.6 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का काम सितंबर 2010 तक पूरा होना था, लेकिन अत्यधिक देरी के कारण जहां नगारिकों को परेशानी हुई, वहीं इसकी शुरुआती अनुमानित लागत में भी कई गुना वृद्धि हो गयी।

इसके अलावा, ईडीएमसी की लंबे समय से लंबित शाहदरा झील पुनर्विकास परियोजना को जुलाई 2019 में नई ऊर्जा मिली, जब इस परियोजना को केंद्र सरकार की अमृत (अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन) योजना के तहत लाया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 (पीएमकेवीवाई 3.0) के तहत पूर्वी दिल्ली नगर निगम में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं (ई-कार्ट लाइसेंस के लिए) की अपस्किलिंग के लिए परियोजना शुरु हुई है, जिसमें ई-कार्ट लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को कुशल बनाने के लिए उन्हें स्वच्छता, सुरक्षा, ग्राहक केंद्रितता, डिजिटल लेनदेन और उद्यमिता कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

2019 में ईडीएमसी ने 500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की आसान अनुमति के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉच किया है। अप्रूवल अब बिना किसी ह्यूमन इंटरफेस के ऑनलाइन लिए जा सकते हैं। अमृत के तहत दिल्ली और एनसीआर के निवासियों को पानी की आपूर्ति करने के लिए कदम उठाए गए। अब तक चार शहरी स्थानीय निकायों अर्थात् नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी), पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (उत्तरी डीएमसी) और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में 292 करोड़ रुपये की दस जलापूर्ति परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए नियमितीकरण एक समस्या रही है। संपत्ति के मालिक, जिनके पास पंजीकरण के कागजात नहीं हैं, उन्हें अपनी संपत्ति बेचने या गिरवी रखने में मुश्किल होती है। ऐसे लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री दिल्ली आवास अधिकार योजना (पीएम-उदय) के तहत अनधिकृत कॉलोनियां के लिए प्रावधान किये हैं। सितंबर 2021 तक, पीएम-उदय योजना के तहत लगभग 4,25,033 लोगों ने अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की और लगभग 78,000 लोगों ने आवेदन भरे। इसके अलावा, प्राधिकरण पर्ची के साथ वाहन विलेख लगभग 8,000 हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस योजना के तहत आठ लाख से अधिक घरों को कवर

किया जाएगा।

इसके अलावा, निगमों द्वारा छठ पूजा - एक प्राचीन हिंदू त्योहार के लिए चार दिनों तक व्यापक प्रबंधन किया जाता है। छठ पूजा मनाने वाले लोगों को सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने साफ शौचालय, रोशनी, मोबाइल डिस्पेंसरी, सड़कों की मरम्मत, घाटों को जोड़ने और अन्य बुनियादी व्यवस्थाओं के साथ घाटों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। इसी तरह दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने छठ पूजा के अवसर पर घाटों का विकास किया और 500 से अधिक श्रद्धालुओं को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 40 लाख रुपये खर्च किए है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने छठ पूजा के अवसर पर घाटों का विकास किया।

अक्टूबर 2019 में उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने बंदर पकड़ने वालों (प्रति बंदर) के पारिश्रमिक को 1,200 रुपये से बढ़ाकर 1,800 रुपये कर दिया है। और अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2020 तक कुल 182 बंदरों को असोला भाटी माइंस स्थित वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में भेजा गया। वर्तमान में निगम कुल 14 केंद्र गैर-पालतू कुत्तों की नसबंदी का कार्यक्रम चला रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में कुल 8823 आवारा कुत्तों की नसबंदी की गई और कुल 343 आवारा पशुओं को हरे कृष्ण गोसदन भेजा गया। पशु जन्म नियंत्रण नीति के तहत 23 वार्डों में लगभग 80 प्रतिशत गैर-पालतू कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है। उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों के अंतर्गत वर्तमान में चार आश्रयों में आवारा मवेशियों को भेजा जाता हैं - हरेवाली में गोपाल गौसदन जिसकी क्षमता 3,200 पशुओं की है; बवाना में श्रीकृष्ण गौशाला, जिसमें 7,600 मवेशियों के लिए जगह है; रेवला खानपुर में मानव गौसदन, जिसमें 500 मवेशियों के रहने की व्यवस्था हैं; और सुरहेरा में डाबर हरे कृष्ण गौशाला, जिसकी क्षमता 4,000 है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आवारा मवेशियों को माइक्रोचिप लगाकर एक कोड देने की योजना को मंजूरी दी है जो अधिकारियों को पशु मालिकों की जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके तहत मवेशी छोड़ने वालों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 1,500 कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और वेतन संरचना को मौजूदा 14,000 रुपये से बढ़ाकर लगभग 30,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम 31-3-2017 तक नियुक्त सभी दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए काम शुरु कर दिया है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने मोबाइल आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से सामुदायिक हॉल की ऑनलाइन बुकिंग सेवा को शुरू किया है। साथ ही, निगम अधिकतम उपयोग और रखरखाव के लिए सामुदायिक हॉलों की आउटसोर्सिंग के लिए प्रयास कर रहा है।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को सभी वरिष्ठ नागरिकों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग वर्ग के लोगों को पेंशन प्रदान करने के लिए कहा था, लेकिन आप सरकार ने इस आदेश को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। इसके अलावा, इस मामले को लेकर नगर निगम ने सरकार को कई पत्र लिखे हैं लेकिन यह अभी भी आप सरकार के पास लंबित है।

दिल्ली के नगर निगम ने अपनी ओर से सभी प्रासंगिक कार्य किए हैं और अंतिम निर्णय दिल्ली सरकार के पास लंबित है, जिसे वे इतने लंबे समय से अनदेखा कर रही हैं, जिससे सभी उद्योगों, छोटी इकाइयों और कारखानों को छूट देने की पूरी प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के तहत विधवा महिलाओं के बच्चों के विवाह एवं शोक सभाओं के लिए सामुदायिक केंद्र निःशुल्क उपलब्ध हैं। इसके साथ ही धार्मिक समारोहों के लिए कम्युनिटी सेंटरों का आधा खर्च वहन किया जा रहा है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने 2 सामुदायिक हॉलों को फिर से तैयार किया है और इनकी दरों में बदलाव किए बिना समारोहों के लिए

चित्रः उत्तर डीएमसी में सामुदायिक हॉल

एक अच्छे माहौल के साथ विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। एसएस मोटा सिंह मार्ग और पोसांगीपुर सामुदायिक केंद्रों में नागरिकों की सुविधा के लिए फॉल्स सिलिंग, टाइलिंग, शौचालय, पंखे, रोशनी आदि की व्यवस्था की गयी है। साथ ही निगम ने 16 सामुदायिक केंद्रों की छतों पर सोलर पैनल लगाए हैं।

असंगठित क्षेत्र के लिए पहल

- भारत में असंगठित श्रमिकों की एक बड़ी आबादी है। यह आबादी मुख्य रूप से कृषि, निर्माण, निर्माण और सेवा क्षेत्र में सक्रिय है। अनौपचारिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से पर्याप्त संख्या में श्रमिकों को प्रौद्योगिकी से जोड़ा गया है। असंगठित मजदूर आकस्मिक, मौसमी और बिखरे हुए रोजगार में संलग्न होते हैं, जो संगठित नहीं होते हैं। इसलिए असंगठित श्रमिकों को भारत में सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे वृद्धावस्था पेंशन, ग्रेच्युटी, कर्मचारी राज्य बीमा, कामगार मुआवजा आदि के मुद्दे का सामना करना पड़ रहा है। असंगठित क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- अनौपचारिक क्षेत्रों के लिए श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भारत में असंगठित श्रमिकों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अनौपचारिक क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना और उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाना और असंगठित श्रमिकों के मुद्दों का समाधान करना आवश्यक था। श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने अगस्त 2021 में असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों का डेटाबेस बनाने के लिए अपना ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल करोड़ों असंगठित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के अंतिम मील वितरण की दिशा में भारी बढ़ावा देता है। यह योजना न केवल उन्हें पंजीकृत करती है बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पूरा करने में भी सहायक होगी। कर्मचारी इस कार्ड के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ कहीं भी कभी भी प्राप्त कर सकेगा। पंजीकरण के बाद, कर्मचारियों को PMSBY के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। भविष्य में, इस पोर्टल के माध्यम से असंगठित श्रमिकों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ वितरित किए जाएंगे। आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थितियों में पात्र असंगठित श्रमिकों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए इस डेटाबेस का उपयोग किया जा सकता है।
- दिल्ली के सभी एमसीडी ने इस योजना को लागू करने के लिए कई प्रयास किए हैं और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के लिए कई वार्डों में शिविर लगाकर उनको सहयोग किया है। दिल्ली में कुल 29,10,020 लोगों को पंजीकृत किया गया है और यह है दिन-ब-दिन बढ़ रहा है।
- जब कोविड-19 महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, तो रेहड़ी-पटरी वालों को महामारी के कारण बहुत नुकसान हुआ, लेकिन केंद्र सरकार के साथ दिल्ली के तीनों नगर निगम रेहड़ी-पटरी वालों को समर्थन देने के लिए विभिन्न पहल कर रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए जून 2020 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) शुरू की गई थी। इस योजना के तहत कुल 51,901 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं, जिसकी कुल लागत 52 करोड़ रुपये हैं। इसी तरह पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 6652 रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ दिया है।
- इसके अलावा कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 31 मार्च, 2022 तक रेहड़ी-पटरी वालों पर लगने वाली फीस माफ कर दी है। इस निर्णय से लगभग 55,000 विक्रेताओं को लाभ होगा। इसके अलावा, साप्ताहिक बाजारों में विक्रेताओं के लिए कोविड परीक्षण केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है जो वायरस के जोखिम

को कम करेगा। साथ ही, साप्ताहिक बाजार के दुकानदारों को विभिन्न लाइसेंस दिए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उन सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकें जो उनके लिए उपलब्ध हैं।

- उत्तरी दिल्ली नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले साप्ताहिक बाजार में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान कर रहा है:-
  - » यातायात और स्थानीय पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाए रखने और बाजार में वाहनों को नियंत्रित करने के लिए सूचित किया जाता है।
  - » स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को कोविड के दौरान स्क्रीनिंग की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया जा रहा है।
  - » यह सुनिश्चित करने के लिए लोगों को तैनात किया जा रहा है कि विक्रेता और खरीदार के बीच पर्याप्त दूरी बनी रहे और कोविड अवधि के दौरान एक समय में 2 से अधिक खरीदारों को किसी भी स्टाल पर खड़ा न होने दिया जाए। खरीदारों और विक्रेताओं के बीच दूरी के लिए प्रत्येक स्टाल की उचित मार्किंग सुनिश्चित की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक विक्रेता आम जनता या ग्राहकों द्वारा उपयोग के लिए हैंड सैनिटाइज़र तैयार रखे।
  - » साप्ताहिक बाजार में कचरा/थूकने पर नियंत्रण के लिए डीईएमएस विभाग के कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि साप्ताहिक बाजार में कूड़ेदान उपलब्ध हों।
  - » केंद्र सरकार और नगर निगमों द्वारा असंगठित क्षेत्र के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों ने अनौपचारिक क्षेत्र में बड़े बदलाव लाए। इन मजदूरों को अब केंद्र और राज्य सरकारों की सामाजिक सुरक्षा और रोजगार आधारित योजनाओं का लाभ मिल रहा है। विभिन्न व्यवसायों के श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण है। यह पंजीकरण असंगठित क्षेत्र और रोजगार में श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्यक्रमों और विभिन्न अधिकारों के वितरण और पहुंच की सुविधा प्रदान कर रहा है। जब महामारी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, तो एमसीडी और केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए उपाय रेहड़ी-पटरी वालों को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने में मदद करते हैं।

व्यवस्थित पार्किंग और यातायात प्रबंधन

रोजमर्रा की जिंदगी में पार्किंग सिस्टम बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। हमें अपने घरों, कार्यालयों, मॉल, अस्पतालों और अन्य जगहों पर पार्किंग की जगह चाहिए जहां हम जाते हैं। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, परित्यक्त नीतियों और सब्सिडी के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों में निजी कार के उपयोग की बढ़ती दर, कार पार्किंग को दुनिया भर में परिवहन और यातायात प्रबंधन के लिए मुख्य चिंताओं में से एक बनाने का मुख्य कारण हैं। हाल के वर्षों में हमने प्रौद्योगिकी का विकास देखा है और इसका एक हिस्सा पार्किंग प्रबंधन प्रणालियों में सुधार है। जब पार्किंग क्षेत्र में वाहनों के प्रवाह को नियंत्रित करने की बात आती है तो पार्किंग प्रबंधन प्रणाली न केवल सुविधाजनक बल्कि लचीली होती है। पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थानों की कमी और इसकी बढ़ती मांग एक बड़ी समस्या है। इसका भारत के अधिकांश महानगरों के यातायात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस मुद्दे को हल करने के लिए दिल्ली में व्यवस्थित पार्किंग नीति और यातायात प्रबंधन की आवश्यकता है।

2012-13 में 'दिल्ली मूर्त परिवर्तन परियोजना (डीटीटीपी) पर रिपोर्ट' में लोक नीति शोध केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा दी गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, एमसीडी ने उन सुझावों को लागू किया है और पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए स्वचालित बहुस्तरीय कार पार्किंग का निर्माण किया है। स्वचालित पार्किंग प्रणाली तकनीकी रूप से टिकाऊ है क्योंकि यह प्रणाली यंत्रीकृत है जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। यह वाहनों की संख्या बनाम एकत्र की गई राशि और उस समय की अवधि के लिए डेटा रखता है जिसके लिए वाहन पार्क किया गया था। पूंजी निवेश अधिक होने के बावजूद यह पहल आर्थिक रूप से उपयोगी है। दैनिक संग्रह, जो पार्किंग दरों के आधार पर किया जाता है, वह लाभदायक सिद्ध हुआ है। सभी नगर निगमों द्वारा भीड़-भाड़ वाले स्थानों और बाजार क्षेत्रों में स्वचालित बहुस्तरीय कार पार्किंग का निर्माण कर दिल्ली में पार्किंग प्रबंधन और यातायात की समस्या को हल करने में मदद मिल रही है।

दिल्ली के नागरिकों के लिए 'नो पार्किंग स्पेस' एक बड़ी समस्या है। पार्किंग के लिए सीमित स्थानों की उपलब्ध के कारण नागरिक आमतौर पर सड़कों पर अपनी गाड़ियां खड़ी करने को मजबूर होते है, जो भीड़भाड़ का कारण बनता है। इसलिए, इस समस्या के एक प्रभावी समाधान की आवश्यकता की जा रही थी। भीड़-भाड़ वाली

जगहों जैसे बाजारों और पार्कों में लोगों को पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में तीनों नगर निगमों ने विभिन्न नीतियां बनाईं और पार्किंग और यातायात की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न समाधानों के साथ आए और शहरों में व्यवस्थित पार्किंग प्रदान करने और शहर में यातायात का प्रबंधन करने के लिए कदम उठाए। दिल्ली में नगर निगमों ने इस मुद्दे को हल करने के लिए एक स्वचालित बहुस्तरीय टावर कार पार्किंग का निर्माण किया।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एक निर्धारित समय सीमा के भीतर नागरिकों के लिए पहली स्वचालित मल्टी-लेवल टॉवर कार पार्किंग का निर्माण किया है। निगम ने कृष्णा नगर क्षेत्र में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कराया है। इस आधुनिक कार पार्किंग में 4 टावरों है और प्रत्येक टावर में 17 तल है, जिसमें एक ही समय में 136 कारों को समायोजित किया जा सकता हैं। इसके अलावा, निगम के पास 10,000 वाहनों की पार्किंग की जगह है और अन्य रिक्त स्थान को विकसित करने की योजना पर कार्य चल रहा है। उत्तर नगर निगम ने विभिन्न स्थानों पर 17 बहुस्तरीय पार्किंग व्यव्सथा का निर्माण किया है और कई क्षेत्रों में 3 स्टैक सुविधाओं का निर्माण भी किया जा रहा है। इस मल्टीलेवल कार पार्किंग में एक बार में 12,915 वाहनों के लिए जगह होगी। वर्तमान में उत्तर निगम के अंतर्गत 130 पार्किंग स्थल है।

चित्रः ग्रीन पार्क में स्वचालित बहुस्तरीय टॉवर कार पार्किंग

चित्रः लाजपत नगर स्वचालित पार्किंग

दक्षिण नगर निगम ने दिल्ली में पहली स्वचालित पजल पार्किंग का निर्माण किया है, जिसमें एक बार में 246 वाहनों को रखा जा सकता है। लाजपत नगर में सिर्फ 1 साल की अवधि में 27 करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा, निगम ने राजौरी गार्डन क्षेत्र में पांच मंजिला बहु-स्तरीय कार पार्किंग का निर्माण किया है जो 200 वाहनों को रखने की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा, निगम ने 136 वाहनों की क्षमता के साथ ग्रीन पार्क में एक 17 मंजिला स्वचालित टावर पार्किंग का निर्माण भी किया है।

इसके अलावा निगम ने नजफगढ़ रोड से जोगिंदर सिंह मार्ग से लेकर बीएसईएस कार्यालय जिला केंद्र, जनकपुरी पुलिस स्टेशन के सामने, भारत गैस से दुकान नंबर 15 और 16, ए-3 डीडीए मार्केट सहित लगभग 13 पार्किंग स्थलों में सुधार किया है। इसके अलावा निगम 20 विभिन्न स्थानों पर ऑटोमेटिक मल्टीलेवल कार पार्किंग, 3 अंडरग्राउंड मल्टी लेवल कार पार्किंग की स्थापना कर रहा है और इन सभी को गूगल मैप्स के माध्यम से भी जोड़ेगा।

कोविड-19 के दौरान पहल

वर्ष 2020 में दुनिया कोविड-19 की महामारी की चपेट में आ गई, जिसके कारण नागरिकों और उनके जीवन में बड़ी मुश्किलें आईं और उनका जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। वास्तव में दिल्ली उन राज्यों में से था जो महामारी की चपेट में थे, लेकिन दिल्ली के अधिकारियों के सहज प्रयासों के कारण राष्ट्रीय राजधानी वायरस के खिलाफ मजबूती से खड़ा रही।

विनाशकारी कोविड-19 महामारी ने दुनिया को प्रभावित किया है और कई स्तरों पर अपना प्रभाव छोड़ा है। लेकिन यह दिल्ली एमसीडी के उन 40,035 'सफाई कर्मचारी' के प्रयास ही है, जिनके कारण दिल्ली महामारी पर काबू में सफल रही।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कोविड-19 महामारी की पहली लहर (जून से अक्टूबर 2020) के दौरान हिंदू राव अस्पताल में कोविड रोगियों के लिए 5 आईसीयू बेड और 95 ऑक्सीजन बेड की सुविधा प्रदान की। इसके अतिरिक्त बालक राम अस्पताल में 100 बेड कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया। इसके अलावा, राजन बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन एंड ट्यूबरकुलोसिस (RBIPMT) में एक बार में 120 रोगियों का इलाज किया गया, जिनमें से लगभग सभी गंभीर श्रेणी के थे।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने तीसरी लहर के लिए ऑक्सीजन बेड तैयार किए। आरबीआईपीएमटी और एमवीआईडी अस्पताल में 133 ऑक्सीजन बेड कोविड रोगियों के लिए तैयार किए गए थे, कस्तूरबा अस्पताल और बालक राम अस्पताल दोनों में 50 ऑक्सीजन बेड, जीएलएम अस्पताल में 60 ऑक्सीजन बेड और हिंदू राव में 505 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा एनडीसीएम द्वारा निम्नलिखित बिंदुवार प्रगति की गईः

- 750 से अधिक ऑक्सीजन बिस्तर और 190 वेंटिलेटर किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं।
- नॉर्थ एमसीडी के 6 अस्पतालों में 333 ऑक्सीजन कंसंटेटर लगाए गए।
- हिंदू राव में आईसीयू बेड की संख्या 10 से बढ़ाकर 55 कर दी गई है, जिसमें बच्चों के लिए 20 बेड शामिल हैं। आरबीआईपीएमटी में 10 बिस्तरों वाला आईसीयू और 10 बिस्तरों वाला एचडीयू स्थापित किया जा रहा है।
- 5 बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन का विस्तार किया गया। बालक राम अस्पताल में मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम पूरा होने के करीब है। अस्पतालों के लिए और ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे गए।
- हिंदू राव अस्पताल, आरबीआईपीएमटी, जीएलएम अस्पताल में 1000 एलपीएम क्षमता पीएसए आधारित ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किये गये है।
- हिन्दू राव अस्पताल में 10,000 लीटर (8000 घन मीटर) एलएमओ प्लांट की क्षमता में वृद्धि की गयी है जिससे बिस्तरों की संख्या को बढ़ाया जा सके।
- वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सांद्रक, मल्टी मॉनिटर, इलेक्ट्रिक सक्शन मशीन आदि सहित विद्युत चिकित्सा उपकरणों के उपयोग के लिए अस्पतालों में बिजली के प्वाइंटों में वृद्धि की गयी है। नए स्थापित चिकित्सा उपकरणों के उपयोग के लिए स्वास्थ्यकर्मियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयुष स्टाफ का भी प्रशिक्षण किया गया। हिंदू राव अस्पताल के सभी डीएनबी छात्रों की आईसीयू में अनिवार्य रूप से 2 सप्ताह की पोस्टिंग की गयी, ताकि उन्हें कोविड महामारी की लहर के दौरान आईसीयू वार्ड में तैनात किया जा सके।
- जरूरत पड़ने पर अस्पतालों में तेजी से तैनाती सुनिश्चित करने के लिए पीजी डॉक्टरों की सूची को तैयार किया गया है। अधिक जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए हिंदू राव अस्पताल में इंटर्न (एमबीबीएस) छात्रों की संख्या में वृद्धि की गयी है। तकनीकी पाठ्यक्रमों जैसे लैब तकनीशियन, ओटी तकनीशियन, एक्स रे तकनीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट में इंटर्न छात्रों की संख्या बढ़ायी गयी है।
- उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत जहां कोविड-19 के संदिग्ध मामले सामने आ रहे हैं, वहां पर छिड़काव का कार्य किया जा रहा है। वहीं नागरिकों के आग्रह पर भी इसको अंजाम दिया जा रहा है।
- मेगाफोन/लाउडस्पीकर के माध्यम से जनता को लॉकडाउन दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। इसके साथ ही कोरोना और वेक्टर जनित बीमारियों के संबंध में आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए पोस्टर, हैंड बिल, स्टिकर लगाए गए हैं।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने न केवल रोगियों के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं की खरीद की बल्कि दवाओं के स्टॉक की स्थिति की भी जांच की। आरटीपीसीआर परीक्षण सुविधा स्थापित की गई है और हिंदू राव अस्पताल में कार्यात्मक उत्तर डीएमसी मेडिकल कॉलेज और उत्तरी डीएमसी के 4 अस्पतालों, 05 पॉलीक्लिनिक,

16 एम एंड सीडब्ल्यू केंद्रों में आरटीपीसीआर परीक्षण किया जा रहा है। उत्तर डीएमसी में 93 कोविड टीकाकरण केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं और अब तक 35 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

ईडीएमसी ने कोविड-19 महामारी के दौरान हर घर को सेनेटाइज किया और पूर्वी दिल्ली नगर निगम की सभी डिस्पेंसरियों में मरीजों का इलाज और दवाओं की व्यवस्था की गई। ईडीएमसी क्षेत्र में भी मोबाइल डिस्पेंसरी के माध्यम से दवाओं का वितरण किया गया। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली और उसके आसपास के लोगों के इलाज के लिए 160 बेड को सुरक्षित किया गया। एमपी निधि से दो वेंटिलेटर और 02 आईसीयू बेड खरीदे गए हैं। मरीजों और अस्पताल की सुरक्षा के लिए 75 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

स्वामी दयानंद अस्पताल में 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। स्वामी दयानंद अस्पताल में कोविड अस्पताल में परिवर्तित होने के बाद मरीजों की भारी संख्या को देखते हुए सभी प्रकार के मध्यम और गंभीर रोगियों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया गया और उनके लिए उचित ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। स्वामी दयानंद अस्पताल ने कोविड-19 महामारी के दौरान उच्च स्तर की सुविधाएं और उपचार प्रदान करना जारी रखा जब निजी अस्पतालों ने गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी रोक दी थी। इसके अलावा कोविड-19 से प्रभावित छोटे व्यापारियों के लिए साप्ताहिक बाजार शुल्क माफ कर दिया गया, जिसने मुश्किल समय में लगभग 50,000 लोगों की मदद हुई।

कोविड-19 महामारी के दौरान भारत सरकार ने अपने नागरिकों को उनके घरों में वापस लाने के लिए वंदे मातरम मिशन शुरू किया। इस प्रकार, प्रत्येक व्यक्ति की जांच की जानी थी और इसके लिए ईडीएमसी ने 21 मार्च, 2020 से 22 फरवरी, 2021 तक आईजीआई टर्मिनल -3 हवाई अड्डे पर 5 टीमों को तैनात किया है। प्रत्येक टीम में डॉक्टर, स्वास्थ्य नर्स और मोबाइल टीम शामिल थी।

एम एंड सीडब्ल्यू अनुभाग के कर्मचारी होम आइसोलेशन के तहत कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ऐसे रोगियों के भौतिक सत्यापन के लिए नियमित मूल्यांकन कर रहे थे। संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा इलाज और निगरानी के लिए कोविड-19 रोगियों को दवाएं, पल्स ऑक्सीमीटर भी दिया गया।

ईडीएमसी ने कई अन्य कदम उठाए हैं जिनमें विशेष रूप से शामिल हैं:

- 20 कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों को क्रियाशील बनाया गया।
- कोविड-19 के दौरान निर्बाध रोगी देखभाल सेवाएं प्रदान की। जनवरी 2021 से सितंबर 2021 तक कुल 46680 मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं
- जहां जीटीबी अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में नामित किया गया था, वहीं स्वामी दयानंद अस्पताल को चौबीसों घंटे अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नामित किया गया था।
- लोगों को शारीरिक दूरी, मास्क पहनने और हाथ की

चित्रः एमसीडी अस्पतालों में बिस्तर

चित्रः कोविड केंद्रों में बिस्तर

चित्रः एसडीएमसी में ऑक्सीजन संयंत्र

स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए आईईसी गतिविधियों का आयोजन किया।

- सीमापुरी स्थित प्रसूति गृह का नाम बदलकर मां जानकी मातृत्व गृह कर दिया गया है।
- चांदीवाला, मैटरनिटी होम का जीर्णोद्धार कर पूरी तरह कार्यात्मक बनाया गया है।
- एलोपैथिक औषधालय, करावल नगर का पुनर्निर्माण कार्य 200 लाख रुपये की अनुमानित लागत से पूरा कर लिया गया है और अब यह सुचारू रूप से काम कर रहा है।

साथ ही भारतीय संस्कृति के सूत्र 'नर सेवा ही नारायण सेवा' का अनुसरण करते हुए निगम ने अपने 91 विद्यालयों में भूख निवारण केन्द्र खोले, जहां से पका हुआ भोजन वितरित किया जाता था। इतना ही नहीं, निगम ने अपने 92 निगम विद्यालयों में गेहूं, चावल आदि सहित सूखा राशन वितरित किया है। नाश्ता योजना के तहत अप्रैल 2020 से जून 2020 तक और उसके बाद जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक बैंक खातों में बच्चों को नकद राशि दी गई।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

हम सभी वर्तमान कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए हैं। हालांकि, इस महामारी के प्रभाव और परिणाम गंभीर थे, लेकिन दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा किए गए प्रयासों के कारण नागरिकों को काफी सुविधा हुई। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने निगम के स्कूलों और सामुदायिक भवनों को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर करीब 12 क्वारंटाइन और 175 आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था की। इन आइसोलेशन सेंटरों में 10,321 से अधिक लोगों का इलाज किया है। एसडीएमसी ने एशिया के सबसे बड़े क्वारंटाइन सेंटर का भी निर्माण किया था जिसमें संक्रमित लोगों की सेवा में कई डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और सैनिटाइजेशन कर्मचारी कार्यरत थे। निगम के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के सैंपल लेने का काम कर रहे थे।

रोगी को बेहतर उपचार और घर-घर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए निगम ने 80 से अधिक फ्लू क्लीनिक स्थापित किए हैं, जो दैनिक आधार पर चलते हैं। इन फ़्लू क्लीनिकों के माध्यम से 26 मार्च, 2020 लेकर लगभग 5,51,687 व्यक्तियों को ओपीडी

की सुविधा दी गई और गंभीर होने पर अस्पताल भेजा गया। इसके अलावा निगम ने अपने 2 अस्पतालों अर्थात् पीएसएमएस अस्पताल और टीएनसीएच तिलक नगर को भी आइसोलेशन केंद्रों में परिवर्तित कर दिया है, जिनकी क्षमता क्रमशः 50 और 70 बिस्तरों की है।

महामारी को रोकने के लिए निगमों के आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक विभागों ने 1,57,516 लोगों को आरोग्य काढ़ा (कढ़ा) और 3,57,751 व्यक्तियों को आर्सेनिक 30 दवा वितरित की गयी। निगम के इन प्रयासों से महामारी के खिलाफ लड़ाई मे मजबूती आयी। इसके अलावा नगर निकाय के आयुर्वेद विभाग ने कोविड-19 की रोकथाम में आयुर्वेदिक दवाओं के लक्षणों, रोकथाम और उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कदम उठाए। इस जागरूकता कार्यक्रम का 3,74,315 से अधिक लोगों ने लाभ उठाया है।

महामारी से बचाव की प्रक्रिया में स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए निगम ने अपने नियंत्रण में आने वाले सभी संभव उपकरणों का लगातार उपयोग करते हुए सभी क्षेत्र को पूरी तरह से सैनिटाइज किया है। इस प्रक्रिया में निगम ने निम्नलिखित मशीनों का उपयोग किया हैः

- 400 - मोटरयुक्त पंप
- 893 - पिट्ठू पंप
- 10 - टैंकर स्प्रेयर
- 16 - जेटिंग मशीन
- 16- जल छिड़काव उपकरण
- 02 - ड्रोन

अपने अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए निगम के करीब 22,000 सफाईकर्मी लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे थे। इस प्रकार, निगम ने प्रतिदिन 64,206 कॉलोनियों, 54,894 सार्वजनिक स्थानों और 150 से अधिक नियंत्रण क्षेत्रों को साफ किया है।

निगम का डीईएमएस विभाग आइसोलेशन सेंटरों से ठोस कचरा इकट्ठा करने में लगा हुआ था और इस बात का खास ख्याल रखा गया कि इसका इस तरह से निस्तारण किया जाए कि महामारी आगे न फैले। प्रतिदिन औसतन 3,200 मीट्रिक टन कचरा एकत्र किया जाता था और उसका निपटान किया जाता था। इसके साथ ही निगम ने लगातार सभी क्वारंटाइन, आइसोलेशन सेंटरों से जैविक कचरे को एकत्रित कर कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी (सीबीडब्ल्यूटीएफ) के माध्यम से इसका निस्तारण किया। खाद्य सामग्री की कमी से जूझ रहे लोगों की देखभाल के लिए निगम ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। निगम ने 32 खाद्य आश्रय, 70 पके हुए भोजन केंद्र और 70 कच्चे राशन केंद्र बनाए हुए हैं।

निगम के डॉक्टर दिन-रात न केवल कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का इलाज कर रहे हैं बल्कि अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी प्लाज्मा दान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इसलिए, निगम ने ऐसे संभावित प्लाज्मा दाताओं का एक डेटाबेस तैयार किया है ताकि भविष्य में संक्रमित व्यक्तियों के जीवन को बचाया जा सके। निगम द्वारा संचालित प्रसूति केंद्र 24 घंटे कार्यरत है और गर्भवती महिलाओं को सुविधाएं प्रदान कर रहे है। साथ ही निगम ने टोल फ्री नं. 1800115676 जारी किया था जिस पर निगम के चिकित्सक व निजी क्षेत्र के क्लीनिकल मनोचिकित्सक 15 अप्रैल से लगातार उपलब्ध हैं।

संदर्भ

https://www.dailypioneer.com/2017/delhi/sdmc-dedicates-two-fcts-for-west-zone.html

https://www.hindustantimes.com/delhi-news/in-delhi-s-tagore-garden-sdmc-begins-waste-segregation/story-GY26sBrnnSFobIq7SKognO.html

https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/delhi-5-more-trommel-machines-to-be-acquired-for-bhalaswa-landfill-says-mayor/articleshow/77703612.cms

https://www.hindustantimes.com/cities/in-this-rohini-ward-trash-is-serious-business/story-5nPpDGgf95ED6hKzaNJJEI.html

https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/dhalaos-in-north-delhi-get-fresh-look-with-selfie-point-library/articleshow/79985480.cms

https://www.newindianexpress.com/cities/delhi/2019/nov/14/edmc-to-introduce-smart-classes-in-more-schools-in-delhi-2061584.html

https://indianexpress.com/article/education/delhi-lg-opens-smart-classrooms-sdmc-plans-project-at-14-more-schools/

https://digitallearning.eletsonline.com/2018/04/north-delhi-mcd-launches-smart-classes/

https://indianexpress.com/article/cities/delhi/delhiites-municipal-services-doorstep-civic-bodies-csc-7400421/

https://mcdonline.nic.in/edmcportal/service

https://mcdonline.nic.in/ndmcportal/service

https://mcdonline.nic.in/sdmcportal/service

https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/many-civic-services-in-edmc-areas-go-online/articleshow/81792753.cms

https://www.newindianexpress.com/cities/delhi/2019/may/18/delhis-rani-jhansi-flyover-a-project-that-took-two-decades-to-be-completed-1978642.html

https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/projects-at-shahdara-jheel-east-corpns-zonal-hq-back-in-action/articleshow/75652202.cms

https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1788919

https://www.newindianexpress.com/cities/delhi/2019/nov/18/building-approvals-delhi-civic-bodies-open-web-portal-here-is-everything-you-need-to-know-2063194.html

https://www.livemint.com/news/india/planning-a-house-in-delhi-get-your-building-plan-sanctioned-online-11571195923533.html

https://www.newindianexpress.com/cities/delhi/2019/nov/18/building-approvals-delhi-civic-bodies-open-web-portal-here-is-everything-you-need-to-know-2063194.html

https://www.newindianexpress.com/cities/delhi/2019/nov/18/building-approvals-delhi-civic-bodies-open-web-portal-here-is-everything-you-need-to-know-2063194.html

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1777284

https://housing.com/news/pm-uday-yojana/#:~:text=According%20to%20the%20DDA%2C%20more,under%20the%20PM%2DUDAY%20scheme

https://www.cityspidey.com/news/9912/mayor-holds-meet-to-prepare-edmc-for-chhath-puja

https://navbharattimes.indiatimes.com/metro/delhi/other-news/ghats-being-spruced-up-mobile-toilets-and-dispensaries-being-provided-for-chhath-puja-in-delhi/articleshow/71841015.cms

https://www.hindustantimes.com/delhi-news/chhath-in-delhi-how-yamuna-has-been-spruced-up-for-the-biggest-festival-in-town/story-aSYBcLy91pF8Q8KqUu0mXI.html

https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/ghats-being-spruced-up-mobile-toilets-and-dispensaries-being-provided-for-chhath-puja-in-delhi/articleshow/71838402.cms

https://mcdonline.nic.in/edmcportal/downloadFile/lan_210218104136236.pdf

https://www.hindustantimes.com/delhi-news/losing-monkey-catchers-need-to-raise-their-salary-north-mcd/story-sy3VBxFEKRkmzMWf6EoeKJ.htm

http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/77176345.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst.

https://theprint.in/india/microchips-coming-soon-for-delhi-cattle-owners-abandoning-them-will-pay-rs-25000-penalty/605972/

https://theprint.in/india/microchips-coming-soon-for-delhi-cattle-owners-abandoning-them-will-pay-rs-25000-penalty/605972/

https://www.bhaskar.com/local/delhi-ncr/news/east-mcd-begins-the-process-of-regularizing-the-replacement-sweepers-128418703.html
https://indianexpress.com/article/cities/delhi/east-delhi-body-speeds-up-regularisation-of-sanitation-workers-5538582/
https://www.business-standard.com/article/pti-stories/ndmc-issues-letters-to-regularise-18-sanitation-workers-119091701077_1.html
https://www.business-standard.com/article/news-ians/delhi-government-will-accommodate-mcd-pensioners-116012001244_1.html
https://www.etvbharat.com/hindi/delhi/state/east-delhi/east-delhi-municipal-corporation-started-two-cng-crematoriums-at-ghazipur-crematorium/dl20210521015412613
https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/corpns-plan-more-cng-furnaces-at-crematoria/articleshow/85138658.cms
https://www.amarujala.com/delhi/now-the-use-of-cow-dung-cakes-will-be-done-in-cremation-northern-and-eastern-municipal-corporation-approved
https://indianexpress.com/article/cities/delhi/delhi-cremation-grounds-furnaces-6448067/
https://www.newindianexpress.com/cities/delhi/2021/apr/22/north-delhi-municipal-corporation-plans-new-system-to-streamline-last-rites-2293166.html
https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/civic-bodies-strengthen-their-infra-to-fumigate-city-rwas-not-convinced/articleshow/87319135.cms
https://nvbdcp.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=431&lid=3715
http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/176/AU3155.pdf
https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1579464
https://mcdonline.nic.in/edmcportal
https://mcdonline.nic.in/sdmcportal/
https://mcdonline.nic.in/ndmcportal/
http://www.millenniumpost.in/delhi/sdmc-introduces-191-new-public-toilets-433990
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2FhMmRmMjAtZDIzOS00ZWU2LWE1NGQtMDhiODA2ODVlY2EyIiwidCI6IjE1NjUyNDgwLTA3MjUtNDk2Yy1hOTg0LWRlYjFlZGExNjFhMCJ9
https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Home/PMSDashboard
https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/east-corpn-not-to-charge-fees-from-weekly-market-vendors-due-to-pandemic/articleshow/83968188.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/sdmc-to-start-survey-of-hawkers-at-lajpat/articleshow/84623778.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/civic-bodies-ready-strict-norms-for-weekly-markets/articleshow/82108763.cms
http://www.millenniumpost.in/delhi/north-mcd-to-register-weekly-market-street-vendors-294301
https://www.jagran.com/delhi/new-delhi-city-ncr-delhi-weekly-market-news-north-delhi-municipal-corporation-will-give-license-to-shopkeepers-of-weekly-markets-21404215.html
https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/edmc-to-make-space-for-1500-vehicles-by-20/articleshow/68103171.cms#:~:text=At%20present%2C%20EDMC%20has%20parking%20space%20for%2010%2C000%20vehicles.
https://www.amarujala.com/delhi-ncr/multilevel-parking-facility-in-krishna-nagar-market-from-today
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/70916758.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
https://www.hindustantimes.com/cities/delhi-news/north-mcd-to-create-parking-slots-for-13000-cars-101610309860393.html
https://indianexpress.com/article/cities/delhi/delhi-lajpat-nagar-gets-puzzle-parking-with-space-for-246-cars-7217539/
http://www.millenniumpost.in/delhi/automated-multi-level-car-parking-inaugurated-in-rajouri-garden-300156
https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/delhis-first-automated-tower-parking-site-opens-in-green-park/articleshow/79419663.cms
https://mcdonline.nic.in/edmcportal/downloadFile/13.8.20_20081306070888.pd
https://www.cityspidey.com/news/3876/east-delhi-s-c-d-waste-plant-recycles-500-mt-of-debris-every-day
https://mercomindia.com/ntpc-edmc-jv-waste-to-energy/
https://www.business-standard.com/article/news-cm/ntpc-sets-up-jv-company-ntpc-edmc-waste-solutions-120060101442_1.html
https://www.newindianexpress.com/cities/delhi/2019/aug/01/north-mcd--to-set-up-solar-plants-in-200-govt-schools-2012312.html

लोक नीति शोध केन्द्र (पीपीआरसी)

पीपी-66, डॉ. मुखर्जी स्मृति न्यास, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
संपर्कः 011-23381844 ईमेलः contact@pprc.in वेबः www.pprc.in
फेसबुकः PPRCIndia ट्विटरः @PPRCIndia